



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

र. 224]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 3, 2012/आश्विन 11, 1934

No. 224]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 3, 2012/ASVINA 11, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटन रोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2012

वषय : भारत में चीन गणराज्य, हांगकांग, सिंगापुर तथा चीनी ताइपेई से कम्पैक्ट डिस्क रिकार्डबल (सीडीआर) पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा अनंतिम वित्तपोषण।

सं. 15/4/2011-डीजीएडी.—क. पृष्ठभूमि

1. जबकि उपर्युक्त नियम को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा जाएगा), ने चीन गणराज्य, हांगकांग, सिंगापुर तथा चीनी ताइपेई में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित कम्पैक्ट डिस्क-रिकार्डबल सीडीआर के तथाकथित पाटन की दिनांक 4 अप्रैल, 2006 को पाटनरोधी जांच आरंभ की थी और दिनांक 28 अगस्त, 2006 को प्राधिकारी के प्राथमिक जांच परिणामों के आधार पर सीमा-शुल्क विभाग की अधिसूचना दिनांक 6 अक्टूबर, 2006 की अधिसूचना सं. 105/2006-सीयूएस के तहत चीन गणराज्य, हांगकांग, सिंगापुर तथा चीनी ताइपेई से कम्पैक्ट डिस्क रिकार्डबल के आयात पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। अंतिम जांच परिणामों को दिनांक 2 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना के तहत अधिसूचित किया गया था और राजस्व विभाग ने दिनांक 29 जून, 2007 की अधिसूचना सं. 78/2007-सीयूएस के तहत संबंधित देश से संबंधित सामान पर पाटनरोधी शुल्क लगाया।
2. और जबकि, निर्दिष्ट प्राधिकारी, को अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार कम्पैक्ट डिस्क रिकार्डबल के निर्माता की ओर से स्टोरेज मीडिया प्रॉडक्ट्स मैनुफैक्चरर्स एंड मार्केटर्स बेलफयर एसोसिएशन से इस आधार पर संबंधित सामान पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा, वृद्धि करने तथा जारी रखने का अनुरोध करते हुए एक व्यवहारिक आवेदन प्राप्त हुआ कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की सम्भावना है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस बात की जांच करने के लिए कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने से पाटन अथवा क्षति जारी रहेगी अथवा इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 4 अक्टूबर, 2011 की एक सार्वजनिक सूचना संख्या 15/4/2011-डीजीएडी जारी की।
3. और जबकि, दिनांक 29 जून, 2007 की अधिसूचना सं. 78/2007-सीयूएस के तहत अधिसूचित पाटनरोधी शुल्क को अधिनियम की धारा 9(क) (5) के अनुसार दिनांक 14 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या 100/2011-सीमा-शुल्क के तहत दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 तक बढ़ा दिया गया।

4. जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई :

- (i) प्राधिकारी ने संबंधित देशों के दूतावासों, संबंधित देशों के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों, ज्ञात आयातकों तथा उनके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार अन्य इच्छुक पक्षों को दिनांक 4 अक्टूबर, 2011 को अधिसूचना की प्रतियां भेजी। इस जांच के पक्षकारों से निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावलियों के उत्तर भेजने एवं लिखित में अपने विचार प्रकट करने का अनुरोध किया गया था। संबंधित देशों के दूतावासों को इस अनुरोध के साथ ज्ञात निर्यातकों/निर्माताओं की एक सूची सहित पत्र एवं प्रश्नावलियों की प्रतियां भी भेजी गई कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावलियों के उत्तर देने के लिए संबंधित देशों के निर्यातकों/निर्माताओं को परामर्श दें।
- (ii) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6(3) के अनुसार संबंधित देशों के दूतावों एवं ज्ञात निर्माताओं तथा/अथवा निर्यातकों को प्रश्नावलियों को अगोपनीय भाग की प्रतियां प्रदान की। अन्य इच्छुक पक्षकारों के अनुरोध पर अगोपनीय आवेदन की एक प्रति भी उपलब्ध कराई गई थी।
- (iii) प्राधिकारी ने संबंधित देशों की सरकार को तथा ज्ञात निर्यातकों/निर्माताओं को नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना प्रदान करने के लिए एक प्रश्नावली भेजी थी। तथापि, संबंधित देशों के किसी भी निर्यातक/निर्माता ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं भेजा।
- (iv) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना प्रदान करने के लिए ज्ञात आयातकों अथवा प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी गई थी। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के औद्योगिक प्रयोक्ताओं को पाटन, क्षति व दुर्घटना के संबंध में जांच से संबंधित आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने अवसर प्रदान किया। तथापि किसी भी आयातक ने प्रश्नावली को उत्तर नहीं भेजा।
- (v) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से पिछले तीन वर्षों एवं जांच की अवधि के लिए संबंधित सामान के आयात के ब्यौरे देने का अनुरोध किया गया था। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े इम्पैक्स से लिए गए थे।
- (vi) प्राधिकारी ने संगत सूचना मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए इच्छुक पक्षकारों को एक अवसर प्रदान करने के लिए दिनांक 6 मार्च, 2012 एक जन सुनवाई रखी जिसमें घरेलू उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में स्टोरेज मीडिया प्रॉडक्ट्स मैनुफैक्चरर्स एंड मार्केटर्स वेल्फेयर एसोसिएशन के सदस्य ने भाग लिया था। जन सुनवाई में भाग लेने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप में प्रस्तुत सूचना को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का परामर्श दिया गया।

निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इच्छुक पक्षकारों से प्राप्त इन लिखित प्रतिवेदनों पर विचार किया। तथापि, किसी भी उत्पादक/निर्यातक अथवा आयातक ने जन सुनवाई में भाग नहीं लिया और इसीलिए कोई भी लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच के दौरान इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना/साक्ष्य एवं तर्कों पर प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच की संगतता के अनुसार समुचित रूप से विचार किया गया है।

(vii) जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना/साक्ष्य एवं तर्कों पर वर्तमान जांच की संगतता और समर्थन में दिए गए साक्ष्य के अनुसार प्राधिकारी द्वारा जांच परिणामों में समुचित रूप से विचार किया जाएगा।

(viii) प्राधिकारी जांच की अवधि के दौरान प्रदान की गई ऐसी सूचना की सटीकता के बारे में स्वयं संतुष्ट है, जिन पर ये जांच परिणाम आधारित हैं। उस प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने संगतता और आवश्यकता के अनुसार घरेलू उद्योग की स्थल पर ही पुष्टि की। घरेलू उद्योग से क्षति के बारे में अतिरिक्त/अनुपूरक ब्यौरे मांगे गए, जो प्राप्त भी हो गए थे।

(ix) उपर्युक्त नियम 16 के अनुसार ज्ञात इच्छुक पक्षकारों को इन जांच परिणामों के अनिवार्य तथ्य/आधार का प्रकटीकरण कर दिया गया था और इन पर प्राप्त टिप्पणियों अंतिम जांच परिणामों में विचार कर लिया गया है।

(x) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय भाग, प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित एक सार्वजनिक फाइल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया है और नियम 6(7) के अनुसार इच्छुक पक्षकारों के निरीक्षण के लिए प्रकट कर दिया है।

(xi) सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (जीएएपी) और आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर उत्पादन की ईष्टतम लागत और भारत में संबंधित सामान तैयार करने व बिक्री करने की लागत निकालने के लिए लागत की जांच की गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटन रोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को ठीक करने के लिए पर्याप्त होगा।

(xii) *** से तात्पर्य एक इच्छुक पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना से है जिसे प्राधिकारी द्वारा नियमों के तहत गुणदोष आधार पर विचार किया गया है।

(xiii) 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 (12 माह) की अवधि की जांच की गई थी और इसे जांच की अवधि (पीओआई) के रूप में उल्लेख किया गया है। क्षति विश्लेषण के प्रसंग में जांच में 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं जांच की अवधि (पीओआई) को शामिल किया गया है।

(xiv) जहां कहीं इच्छुक पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान सूचना लेने से मना किया है अथवा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है अथवा जांच में पर्याप्त बाधा डाली है, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणामों में दर्ज किया है।

(xv) इच्छुक पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्टि होने पर प्राधिकारी ने आवश्यकतानुसार गोपनीयता प्रदान की है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य इच्छुक पक्षकारों को प्रकट नहीं की है। जहां कहीं भी संभव सका गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का अगोपनीय भाग प्रदान करने का निदेश दिया गया था।

विचाराधीन उत्पाद और समान सामान

5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन, हांगकांग, सिंगापुर व चीनी ताइपेई (वर्तमान जांच में संबंधित देशों के रूप में उल्लिखित) से निर्मित अथवा निर्यातित कम्पैक्ट डिस्क रिकार्डबल (वर्तमान जांच में सीडीआर अथवा संबंधित सामान के रूप में उल्लिखित) है।
6. सीडीआर एक पॉलिकारबोनेट डिस्क है, जिसमें सूचना लिखने व पढ़ने के लिए लेजर बीम को निर्देशित करने के लिए एक तरफ स्पाइरल ग्रूव है। डिस्क पर स्पाइरल ग्रूव के साथ वेजीटेबल आधारित आर्गेनिक डाई की एक बहुत ही महीन परत चढ़ी है और उसके बाद एक पतली, चांदी, चांदी की मिश्रित धातु अथवा सोने की प्रतिबिंबित परत चढ़ी है। अंत में धातु परावर्तक के सिरे पर एक फोटो-पॉलिमराइजेबल रोगन लगाया गया है और परा-बैंगनी प्रदीपन लगाया गया है। ऐसी डिस्क पर रिकार्डिंग केवल एक बार हो सकती है और इसीलिए डिस्क को डब्ल्यूओआरएम (राइट वंस रीड मैनी टाइम्स) कहा गया है। यह डिस्क डिजिटल डाटा अथवा म्युजिक के लिए एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम है।

घरेलू उद्योग के विचार

7. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

(i) वर्तमान जांच चीन गणराज्य के निर्माताओं तथा/अथवा निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में कम्पैक्ट डिस्क – रिकार्डबल के पाटन के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की समीक्षा, वृद्धि करने तथा इसे जारी रखने के लिए है। चूंकि यह एक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद पर उसी तरह विचार किया जाए जैसा कि प्रारंभिक जांच में किया गया है।

(ii) इस जांच में विचाराधीन उत्पाद कम्पैक्ट डिस्क – रिकार्डबल (सीडीआर) है। सीडीआर एक पॉलिकारबोनेट डिस्क है, जिसमें सूचना लिखने व पढ़ने के लिए लेजर बीम को

निर्देशित करने के लिए एक तरफ स्पाइरल ग्रूव है। डिस्क पर स्पाइरल ग्रूव के साथ वेजीटेबल आधारित आर्गेनिक डाई की एक बहुत ही महीन परत चढ़ी है और उसके बाद एक पतली, चांदी, चांदी की मिश्रित धातु अथवा सोने की प्रतिबिंबित परत चढ़ी है। अंत में धातु परावर्तक के सिरे पर एक फोटो-पॉलिमराइजेबल रोगन लगाया गया है और परा-बैंगनी प्रदीपन लगाया गया है। ऐसी डिस्क पर रिकार्डिंग केवल एक बार हो सकती है और इसीलिए डिस्क को डब्ल्यूओआरएम (राइट वंस रीड मैनी टाइम्स) कहा गया है। यह डिस्क डिजिटल डाटा अथवा म्यूजिक के लिए एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम है।

(iii) घरेलू उत्पाद निर्यातकों द्वारा निर्यातित/उत्पादित संबंधित सामान का समान उत्पाद है जिनमें दोनों में कोई खास अंतर नहीं है और ये भौतिक व रासायनिक गुणों, विनिर्माण प्रक्रिया व प्रौद्योगिकी, कार्य व उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत, संवितरण व विपणन तथा कर शुल्क वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनात्मक है।

(iv) घरेलू उद्योग द्वारा तैयार माल पाटन रोधी नियमों के तात्पर्य से सदृश सामान है।

आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों एवं अन्य इच्छुक पक्षकारों के विचार

8. किसी भी आयातक, उपभोक्ता, निर्माता एवं अन्य इच्छुक पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद, समान उत्पाद तथा वर्तमान जांच के क्षेत्र के संबंध में कोई टिप्पणी या अनुरोध नहीं किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

9. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद, चीन, हांगकांग, सिंगापुर व चीनी ताइपेई (वर्तमान जांच में संबंधित देशों के रूप में उल्लिखित) से निर्मित अथवा निर्यातित कम्पैक्ट डिस्क रिकार्डबल (सीडीआर) (वर्तमान जांच में सीडीआर या अथवा संबंधित उत्पाद के रूप में उल्लिखित है।) विचाराधीन उत्पाद वहीं है जिस पर मूल जांच में विचार किया गया है।

10. कम्पैक्ट डिस्क – रिकार्डबल को सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 85 के अंतर्गत उप शीर्षक 8523 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण मात्र सूचक के रूप में है न कि जांच के क्षेत्र पर बाध्य है।

11. जांच आरंभन अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद की क्षेत्र निम्नानुसार विनिर्दिष्ट किया गया था:

5. सीडीआर एक पॉलिकारबोनेट डिस्क है, जिसमें सूचना लिखने व पढ़ने के लिए लेजर बीम को निर्देशित करने के लिए एक तरफ स्पाइरल ग्रूव है। डिस्क पर स्पाइरल ग्रूव के साथ वेजीटेबल आधारित आर्गेनिक डाई की एक बहुत ही महीन परत चढ़ी है और उसके बाद एक पतली, चांदी, चांदी की मिश्रित धातु अथवा सोने की प्रतिबिंबित परत चढ़ी है। अंत में

धातु परावर्तक के सिरे पर एक फोटो-पॉलिमराइजेबल रोगन लगाया गया है और परा-बैंगनी प्रदीपन लगाया गया है। ऐसी डिस्क पर रिकार्डिंग केवल एक बार हो सकती है और इसीलिए डिस्क को डब्ल्यूओआरएम (राइट वंस रीड मैनी टाइम्स) कहा गया है। यह डिस्क डिजीटल डाटा अथवा म्युजिक के लिए एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम है।

12. अभिलेखों के साक्ष्य और जांच आरंभन अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को पहले विचार किए गए क्षेत्र के समान ही रखना उचित समझा।
13. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा तैयार सामान संबंधित देशों से तैयार और / अथवा निर्यातित सामान के समान माना जा सकता है, यह उल्लेखनीय है कि प्राधिकारी द्वारा मामले की जांच की गई है और प्राधिकारी को ऐसा कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है जो प्राधिकारी के पूर्व निर्धारण का विरोध करता हो। जांच के आधार पर प्राधिकारी ने यह पाया कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामग्री नियम के तात्पर्य से संबंधित देशों में आयातित अथवा उत्पादित उत्पाद के समान है।

घरेलू उद्योग

घरेलू उद्योग के विचार

14. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

(i) आवेदन, कम्पैक्ट डिस्क – रिकार्डेबल की ओर से स्टोरेज मीडिया प्रॉडक्ट्स मैनुफैक्चरर्स एंड मार्केटर्स वेल्फेयर एसोसिएशन द्वारा दाखिल किया गया है। इसकी एक सदस्य कंपनी, मैसर्स मोसरबेयर इंडिया लि. ने संगत विक्षीय सूचना उपलब्ध कराई है।

(ii) याचिकाकर्ता के अलावा भारत में सीडीआर के सात अन्य ज्ञात उत्पादक हैं जो कुल उत्पादन में अधिक योगदान नहीं देते और वे न तो वर्तमान याचिका का विरोध करते न ही समर्थन करते हैं। याचिकाकर्ता सभी प्रकार के ऐसे सीडीआर बनाने के लिए सक्षम हैं, जो आयात के लिए समान उत्पाद हैं और इसीलिए उनका कुल उत्पादन में 91.8 प्रतिशत योगदान है।

निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं तथा अन्य पक्षकारों के विचार

15. किसी भी अन्य इच्छुक पक्षकार ने इस संबंध में कोई भी अनुरोध दाखिल नहीं किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

16. नियम 2(ख) के अनुसार

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ केवल शेष उत्पादकों के उल्लेख के रूप में निकाला जाएगा।"

17. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना अनुसार, "याचिकाकर्ता कंपनी" का उत्पादन भारत में संबंधिता सामान का 91.8 प्रतिशत उत्पादन बनता है, अतः भारतीय उत्पादन में उनका प्रमुख हिस्सा है। प्राधिकारी का मानना है कि मैसर्स मोसरबेयर इंडिया लि. नियम के तात्पर्य से घरेलू उद्योग है।

अन्य मामले

घरेलू उद्योग के विचार

18. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित सूचित किया है :

(i) याचिका हर तरह से परिपूर्ण है और जांच आरंभ होने के उपरांत प्राधिकारी को पर्याप्त व सही साक्ष्य उपलब्ध कराए गए।

(ii) प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली का किसी भी निर्यातक ने उत्तर नहीं भेजा। अतः निर्यातकों को नियम 6(8) के तहत असहयोगी माना जाए और प्राधिकारी सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार कार्रवाई करे।

(iii) वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को देखते हुए, संबंधित देशों से आयात, जांच अवधि के दौरान गिरकर निचले स्तर पर आ गए। तथापि, इंडोनेशिया से आयात में जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। यह उल्लेख करना जरूरी है कि इंडोनेशिया से आयात "पीटी डायनाटेक परकासा" से होता है, जो जनरल मैग्नेटिक्स लिमिटेड, इंडोनेशिया की एक क्षेत्रीय निर्माता सुविधा है। जनरल मैग्नेटिक्स लि. कंपनी सिंगापुर में पंजीकृत कार्यालय वाली कंपनी है। दो कंपनियां संबंधित हैं। अतः वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों को देखते हुए यद्यपि यह कंपनी वर्तमान में इंडोनेशिया के द्वारा निर्यात कर रही है लेकिन कंपनी पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति पर सिंगापुर से उत्पाद निर्यात करेगी।

निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं एवं अन्य इच्छुक पक्षकारों के विचार

19. किसी भी अन्य इच्छुक पक्षकार ने इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

20. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इच्छुक पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोध को नोट किया है और नियमानुसार अंतिम जांच परिणामों में उपयुक्त शीर्षकों के अंतर्गत मामलों की जांच की गई है।

अनुबंध - 2

पाटन और पाटन मार्जिन की गणनापाटन मार्जिनघरेलू उद्योग के विचार

21. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है :

(i) याचिकाकर्ता का दावा है कि चीन को सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन से गैर-बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया जाए। इसके अतिरिक्त, किसी भी चीनी उत्पादक अथवा निर्यातक से बाजार अर्थव्यवस्था मानने की कोई भी दावा नहीं है। किसी भी चीनी निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया है और न ही बाजार अर्थव्यवस्था मानने का दावा किया है। ऐसे मामले में अनुबंध-1 के पैरा 8 को लागू करना और यह मानने का प्रश्न ही नहीं उठता कि क्या चीनी कंपनियां बाजार अर्थव्यवस्था माने जाने की पात्र हैं या नहीं।

(ii) मूल जांच में प्राधिकारी ने चीन गणराज्य से उत्तर देने वाले किसी भी निर्यातक को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया है।

(iii) वर्तमान जांच अवधि में किसी भी विचाराधीन उत्पाद का अयात नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां पर निरंतर आयात नहीं है, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालेगा कि कोई भी निरंतर पाटन नहीं हो रहा। तथापि, जांच अवधि में निरंतर आयात न होने का अर्थ यह नहीं है कि प्राधिकारी यह निर्धारित करे कि क्या पाटन की पुनरावृत्ति हो सकती है। याचिकाकर्ता ने अन्य देशों का भी उल्लेख किया है, जहां पर कि जांच अवधि में निर्यात न होने पर भी पाटनरोधी शुल्क को आगे बढ़ाया गया है।

(iv) निम्नलिखित से पाटन की पुनरावृत्ति की सम्भावना सिद्ध हुई है :

क. पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने से पाटन की पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को तीव्र क्षति होने की सम्भावना है। समीक्षा जांच का समग्र प्रयोजन यह देखना नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जरूरी है या नहीं बल्कि यह देखना है कि ऐसे शुल्क के अभाव में पाटन में वृद्धि होगी और घरेलू उद्योग पर असर पड़ने की सम्भावना बनेगी।

ख. संबंधित देशों से आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पेशकश की गई कीमतों और विदेशी उत्पादकों की कीमत सूची के साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि आयातों का पहुंच मूल्य सामान्य मूल्य से पर्याप्त कम होगा। इसके अतिरिक्त ये सूची मूल्य अथवा पेश मूल्य हैं और इन कीमतों पर काफी मोलभाव किया जा सकता है। अतः इन कीमतों से काफी कम कीमतें होने की सम्भावना रहेगी।

ग. जिस कीमत पर संबंधित देश से भारत में डीवीडीआर आयात किया जा रहा है, वह ऐसा न्यूनतम मूल्य है, जिस पर संबंधित देशों के उत्पादक भारतीय बाजार में उत्पाद का निर्यात करेंगे। अतः भारत में प्रत्यक्ष लदान न होने के कारण यह उपयुक्त होगा कि जिस कीमत पर डीवीडीआर का भारत में निर्यात किया गया है, वह कीमत निर्धारित की जाए। यद्यपि डीवीडीआर की कीमत सामान्यतः सीडीआर की कीमत से अधिक है, जो कीमत का अंतर नज़रअंदाज़ कर दिया जाए, तो भी डीवीडीआर के आयात मूल्य से वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने पर पाटन होने की सम्भावना बनती है। इसके अतिरिक्त यदि इन्हीं कीमतों पर आयात बताया जाए तो घरेलू उद्योग का निष्पादन और भी खराब स्थिति में होगा।

घ. हाल ही में सीडीआर का आयात मूल्य 341 रु. पर होने की सूचना दी गई है। याचिकाकर्ता द्वारा पहले पेशकश की गई कीमत तुलनात्मक अथवा उससे कम है। इसके अलावा, यह कीमत प्रत्येक संबंधित देश में सामान्य मूल्य से स्पष्टतया कम है। वर्तमान में जिस कीमत पर तीसरे देश से सामग्री निर्यात की गई, उसे देखते हुए यह स्पष्ट है कि संबंधित विदेशी उत्पादक भारतीय बाजार में बेहतर कीमत नहीं पा सकते। ऐसे देशों से आयात इन्हीं कीमतों पर होगा। संबंधित देशों से इन कीमतों पर निर्यात किया जाए तो घरेलू उद्योग का निष्पादन भी पर्याप्त रूप से खराब होगा।

ड. वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को देखते हुए, संबंधित देशों से आयात, जांच अवधि के दौरान गिरकर निचले स्तर पर आ गए। तथापि, इंडोनेशिया से आयात में जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। यह उल्लेख करना जरूरी है कि इंडोनेशिया से आयात "पीटी डायनाटेक परकासा" से होता है, जो जनरल मेग्नेटिक्स लिमिटेड, इंडोनेशिया की एक क्षेत्रीय निर्माता सुविधा है। जनरल मेग्नेटिक्स लि. कंपनी सिगापुर में पंजीकृत कार्यालय वाली कंपनी है। दो कंपनियां संबंधित हैं। अतः वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों को देखते हुए यद्यपि यह कंपनी वर्तमान में इंडोनेशिया के द्वारा निर्यात कर रही है लेकिन कंपनी पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति पर सिगापुर से उत्पाद निर्यात करेगी।

च. इन तथ्यों को देखते हुए कि सीडीआर और डीवीडीआर निर्माण सुविधाएं परस्पर परिवर्तनीय हैं, एक जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है, एक जैसी कच्ची सामग्री का उपयोग होता है, डीवीडीआर के उत्पादन में इसका प्रयोग करने हेतु निर्माता अपनी उत्पादन श्रृंखला में सामान्य परिवर्तन कर सकते हैं अतः पाटन और क्षति की सम्भावना के आकलन के लिए सीडीआर और डीवीडीआर की क्षमताओं को परस्पर परिवर्तनीय समझ कर देखा जाए। संबंधित देशों में सीडीआर और डीवीडीआर के निर्माता अधिकांशतः वही हैं, जो इस बात का समर्थन करते हैं कि शुल्क हटाए जाने पर ये निर्माता सीडीआर का पाटन करेंगे क्योंकि सीडीआर और डीवीडीआर दोनों ही आयातों पर वर्तमान में पाटनरोधी शुल्क लगाया जा रहा है।

- छ. प्राधिकारी ने सीडीआर और डीवीडीआर के संबंध में चार जांच की हैं। सभी जांच में इन उत्पादों का पाटन दर्शाया गया है, इन उत्पादकों द्वारा पाटन की नीति अपनाई जा रही है। पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने पर ये निर्यातकों को भारत में उत्पाद के पाटन का एक बड़ा अवसर प्राप्त होगा, जिससे घरेलू उद्योग के बाजार का हिस्सा घट जाएगा। घरेलू उद्योग उत्पाद की मांग में गिरावट के कारण पहले से ही हानि में है। घरेलू उद्योग के लिए उपलब्ध बाजार के अवसर यदि पाटित आयात से कम होंगे तो भारतीय उत्पादकों को बड़ा वित्तीय घाटा सहन करना पड़ेगा। अथवा उन्हें अपना व्यापार कम करना पड़ेगा।
- ज. संबंधित देशों के उत्पादक संबंधित सामानों का उत्पादन करने के लिए भारी क्षमताएं रखते हैं। उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है कि संबंधित देशों के उत्पादकों के पास अत्यधिक क्षमताएं हैं। यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो संबंधित सामान के आयात में और भी वृद्धि होगी।
- झ. संबंधित देशों के अधिकांश उत्पादकों का अतिरिक्त क्षमता के साथ उत्पाद के निर्यातों पर निर्भर रहना पड़ता है जो संबंधित देशों में निर्माताओं के निर्यात से विकसित होती है। शुल्क हटाए जाने पर इन निर्यातकों द्वारा पाटित मूल्य पर भारत में अपना निर्यात बढ़ाने की सम्भावना है।
- ञ. यदि विचाराधीन उत्पाद के आयातों के रुख का विश्लेषण किया जाता है तो यह स्पष्ट होगा कि पहले भी विभिन्न देशों द्वारा निरंतर पाटन किया जाता रहा है। यदि कुछ देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो दूसरे देशों से पाटन शुरू हो जाएगा। आयातों में परिवर्तन से स्पष्ट है कि वैश्विक निर्माताओं के पास अतिरिक्त क्षमताएं हैं। संबंधित देशों पर पाटन रोधी शुल्क समाप्त किए जाने पर पाटित वस्तुओं का आयात एक सार्थक दर पर भारतीय बाजार में प्रवेश होने की सम्भावना है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
- ट. विचाराधीन उत्पाद के लिए भारतीय बाजार में कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता है। उपभोक्ता को यदि कीमतों में अंतर मिलता है तो वे अपने स्रोत बंद कर सकते हैं। ऐसा होने पर बाजार में संबंधित देशों के कम मूल्य के आयात की उपलब्धता होने से निश्चय ही आयात की ओर रुख करेंगे, जिससे घरेलू उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
- ठ. वर्तमान जांच में पिछले व हाल के आंकड़ों पर विचार करके पाटन की सम्भावना और क्षति की संभावना का निर्धारण किए जाने की जरूरत है। अतः कानून में ऐसी भावी अनुमान के लिए कोई विशेष कार्यपद्धति अथवा समयसीमा नहीं दी गई है।

- उ. ग्रेट ब्रिटेन और इंडोनेशिया से पाटित मूल्यों से संबंधित देशों के माल से संबंधित माल की अदला बदली के स्पष्ट साक्ष्य हैं, जिनके मामले में शुल्कों को हटाने से क्षति होने की संभावना है।
- द. याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त मूल्य पेशकश के साक्ष्य से संबंधित देशों में निर्यातकों के संभावित मूल्य का पता चलता है और उसमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि ये मूल्य घरेलु उद्योग के मूल्यों से काफी कम हैं और इससे कीमतों में भारी कमी आने की संभावना है। मूल्य अस्थिरता का उत्पाद होने के कारण और सीडीआर व डीवीडीआर के उत्पादकों द्वारा पेश कीमतों के रुख को देखते हुए घरेलु उद्योग को अपनी कीमतें कम करनी पड़ेगी, जिससे भारी नुकसान होगी।

अन्य इच्छुक पक्षकारों के विचार

22. संबंधित देश के किसी भी निर्यातक ने वर्तमान जांच के संबंध में कोई उत्तर दाखिल नहीं किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

23. प्राधिकारी ने पाटन एवं उसकी संभावना के निर्धारण की कार्य प्रणाली पर घरेलु उद्योग द्वारा दिए गए तर्कों को नोट किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह चूंकि समीक्षा जांच है इसलिए प्राधिकारी द्वारा शुल्क वापसी होने पर पाटन के जारी रहने और जारी रहने की संभावना अथवा पाटन की पुनरावृत्ति की जांच की जानी अपेक्षित है।

पाटन का जारी रहना अथवा पुनरावृत्ति होना

24. प्राधिकारी ने सभी ज्ञात निर्यातकों को धारा 9क(1)(ग) के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन से प्रश्नावली की प्रतियां भेजी थीं। संबंधित देशों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक और पाटन व पाटन मार्जिन पर भारत में किसी आयातक से कोई भी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्राधिकारी के पास पाटनरोधी नियम 6(8) के अंतर्गत, असंयोगी निर्यातक के लिए उपलब्ध सूचना के आधार पर आगे कार्रवाई करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। नियम के अंतर्गत यह प्रावधान है कि :

“यदि इच्छुक पक्षकार लेने से इंकार करता है अथवा एक तर्कसंगत अवधि के अंदर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं करता है, अथवा जांच में बाधा डालता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच-परिणामों में दर्ज कर सकता है और ऐसी परिस्थितियों में जो वह उपयुक्त समझे केंद्र सरकार को सिफारिश कर सकता है।”

सामान्य मूल्य

25. धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य :

- (i) निर्यातक देश अथवा क्षेत्र में उपयोग के तात्पर्य से उप धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिर्धारित सामान्य व्यापार अवधि में समान वस्तु के लिए तुलनीय कीमत, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश अथवा क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापार अवधि में समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो, अथवा जब निर्यात देश अथवा क्षेत्र के घरेलू बाजार में किसी बाजार विशेष की स्थिति अथवा घरेलू बाजार में कम मात्रा में बिक्री के कारण ऐसी बिक्रियों की एक उचित तुलना अनुमत्य नहीं हो, तो सामान्य कीमत या तो
- (क) जब निर्यातक देश अथवा क्षेत्र अथवा किसी उपयुक्त तीसरे देश से निर्यात किया गया हो, उप धारा (6) के तहत बने नियमों के अनुसार यथानिर्धारित, समान वस्तु की तुलनीय प्रदर्शक कीमत; अथवा
- (ख) उप धारा (6) के तहत बने नियमों के अनुसार यथानिर्धारित, उत्पादक देश में कथित वस्तु के लिए प्रशासनिक बिक्री व सामान्य लागत तथा लाभ को तर्कसंगत रूप से शामिल करके उत्पादन की लागत

चीन गणराज्य

26. प्राधिकारी यह नोट करता है कि वर्तमान जांच में किसी भी चीनी उत्पादक सहयोग नहीं किया है। पाटनरोधी नियमों के अनुबंध के पैरा 7 में प्रावधान है कि :

गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से सदा अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिसमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो उचित समयसीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे

देशों के उपर्युक्त प्रकार से वयन के बारे में बिना किसी अनुचित विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।

27. आवेदक ने यह दावा किया है कि सामान्य कीमत का निर्धारण सपर्युक्त प्रावधानों के आधार पर किया जाए। प्राधिकारी ने अनुलग्नक- 1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार सभी व्यक्तियों से टिप्पणियां मांगी थी।

28. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि चीन को पाटनरोधी नियमों के अनुसार निर्यातक देश अथवा व्यक्तिगत निर्यातकों की धारणा के अधधीन एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-1 के पैरा 8 के तहत, एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का खंडन किया जा सकता है, यदि चीन गणराज्य से निर्यातक पैरा 8 के उपपैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानकों के आधार पर सूचना व पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध करा दें और इसके लिए तथ्य सामने लाए। तथापि, चीन में संबंधित माल के किसी भी निर्यातक / उत्पादक ने प्राधिकारी को न तो सहयोग दिया और न ही पैरा 8 के उपपैरा (3) में यथा उल्लिखित कोई सूचना व साक्ष्य उपलब्ध कराए, जिससे निम्नलिखित मानदंडों पर विचार किया जाए कि क्या :

क कीमतों, लागतों तथा कच्ची सामग्रियों सहित निविष्टियों (इनपुट), प्रौद्योगिकी व श्रम के उपयोगों की लागत, आउटपुट, बिक्री व निवेश के संबंध में चीन गणराज्य में संबधित फर्मों के निर्णय, आपूर्ति व मांग को दर्शाते वाले बाजार संकेतों के उत्तर में और इस संबंध में राज्यों के हस्तक्षेपों के बिना लिए गए हैं और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत बाजार की मूल्यों को पर्याप्त रूप से दर्शाती है। के तहत एकल पक्षीय प्राधिकार समिति ने चर्चा करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी के प्रमाण पत्रों के तहत जिसके तहत कि प्रमुख कि ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिस्मृतियों के मूल्यहास, अन्य हानियों, वस्तु विनिमय तथा ऋणों की प्रतिपूर्ति के द्वारा भुगतान करने के संबंध में पूर्व गैर बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से ली गई सार्थक कमियों के अध्यधीन है।

ग. ऐसी फर्में दिवालियापन तथा सम्पत्ति कानूनों के अधधीन हैं, जो फर्मों के संचालन के लिए कानूनी विश्वास और स्थायित्वता की गारंटी देते हैं और के (15)(1)क 9 1713

29. चूंकि किसी भी चीनी निर्माता ने बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली के उत्तर सहित प्रश्नावली के उत्तर नहीं दिए हैं और गैर बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का खंडन चौहा है, इसलिए कि प्राधिकारी यह विचार करने में असमर्थ हैं कि क्या एक या अधिक चीनी उत्पादकों को वर्तमान मामले में बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान किया जाए। अतः प्राधिकारी चीनी के

29. चूंकि किसी भी चीनी निर्माता ने बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली के उत्तर सहित प्रश्नावली के उत्तर नहीं दिए हैं और गैर बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का खंडन चाहा है, इसलिए के प्राधिकारी यह विचार करने में असमर्थ हैं कि क्या एक या अधिक चीनी उत्पादकों को वर्तमान मामले में बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान किया जाए। अतः प्राधिकारी चीनी के

मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुलग्नक-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य है।

30. प्राधिकारी ने नोट किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर नहीं किया जा सकता क्योंकि उस देश में उत्पादक से संबंधित सूचना प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है।
31. उपर्युक्त को देखते हुए और चीन के उत्पादकों से सहयोग न मिलने के कारण प्राधिकारी ने "किसी अन्य आधार" पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना उचित समझा और चीन में सामान्य मूल्य उत्पादन की लागत के अनुमानों के आधार पर तैयार किया है।
32. प्राधिकारी ने मुख्य कच्ची सामग्री अर्थात् चीन गणराज्य से पोलिकार्बोनेट के आयात की कीमत को समायोजित करके भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर चीन में उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य तैयार किया है।

हांगकांग, ताइवान तथा सिंगापुर

33. हांगकांग, चीनी ताइपेई तथा सिंगापुर के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने निर्धारित प्रश्नावली के तहत सामान्य मूल्य पर कोई प्रतिक्रिया या सूचना नहीं दी है। निर्यातकों के असहयोग के कारण प्राधिकारी ने नियम 6(8) के तहत, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य तैयार किया है। इस प्रयोजन के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री, पॉलिकार्बोनेट की कीमत अंतर्राष्ट्रीय प्रचलित कीमतों के आधार पर तैयार की गई है। अन्य कच्ची सामग्रियों की कीमतें, कच्ची सामग्र के लिए उपयोग मानक तथा अंतरण लागत भारत में घरेलू उद्योग के अनुसार ली गई है। इस वित्तीय लागत के लिए 5 प्रतिशत की दर से लाभ को सामान्य मूल्य तैयार करने में जोड़ा गया है। इस पद्धति द्वारा हांगकांग, चीनी ताइपेई तथा सिंगापुर के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है।

निर्यात कीमत

34. धारा 9 क(1)(ख) के अंतर्गत निर्यात कीमत का अर्थ है :

धारा 9क (1) (ख) के अंतर्गत निर्यात कीमत का तात्पर्य: किसी वस्तु के संबंध में "निर्यात कीमत" का तात्पर्य निर्यातक देश या क्षेत्र से निर्यातित वस्तु की कीमत से है और जहां कोई निर्यात कीमत नहीं है अथवा जहां निर्यातक या आयातक या किसी तीसरे पक्षकार के बीच एसोसिएशन या प्रतिपूरक व्यवस्था के कारण निर्यात कीमत अविश्वसनीय है, वहां निर्यात कीमत का परिकलन उस कीमत के आधार पर निकाला जा सकता है जिस कीमत पर आयातित वस्तु की सर्वप्रथम पुनः बिक्री किसी स्वतंत्र क्रेता को की जाती है और यह उक्त वस्तु की पुनः बिक्री किसी स्वतंत्र क्रेता को नहीं की जाती है या आयातित

रूप में पुनः बिक्री नहीं की जाती है वहां उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे यथोचित आधार पर किया जाए ;

35. प्राधिकारी ने निर्यात कीमत के निर्धारणार्थ सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों के प्रश्नावलियां भेजी। संबद्ध देश के किसी निर्यातक/उत्पादक ने कोई सूचना नहीं दी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों में से किसी से भी कोई ज्ञात आयात नहीं हुआ है अतः भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में वास्तविक कीमत और पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

पाटन का जारी रहना और पाटन मार्जिन

36. तदनुसार, यह निर्धारित किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान देश में उत्पाद का पाटन जारी नहीं रहा है।

पाटन की पुनरावृत्ति की सीमावना - घरेलू उद्योग के अनुरोध

37. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है, इसलिए पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के प्रश्न की जांच निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9(क) (5) के अनुसार की है, जिसमें निम्नानुसार उल्लेख है :

"(5) इस धारा के अंतर्गत लगाया गया पाटनरोधी शुल्क जब तक उसे समाप्त न किया जाए, इस प्रकार से लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा:

परंतु यदि किसी समीक्षा में केन्द्र सरकार का यह मत हो कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति हाने की संभावना है तो वह इस प्रकार से लगाए गए शुल्क की अवधि को समय-समय पर आगे और 5 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है और आगे की ऐसी अवधि इस प्रकार के समय विस्तार के आदेश की तारीख से शुरू होगी।"

बशर्ते यह भी कि जहां 5 वर्ष की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पहले शुरू हुई कोई समीक्षा समय समाप्त होने से पहले किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है तो पाटनरोधी शुल्क ऐसी किसी समीक्षा का परिणाम आने तक एक वर्ष तक की आगामी अवधि तक लागू रहेगा।

38. संगत प्रावधानों के अनुसार निर्णायक समीक्षा जांच में निम्नलिखित पहलुओं की जांच की जानी चाहिए:

क. क्या पाटन जारी है और यदि हां तो क्या पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने से उसके जारी रहने की संभावना है;

ख. यदि पाटन जारी नहीं है तो क्या पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने से पाटन की पुनरावृत्ति होगी;

39. पाटनरोधी नियमों में किसी निर्णायक समीक्षा जांच में पाटन की संभावना की जांच करने की कोई विशिष्ट पद्धति विहित नहीं है। तथापि यदि जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन काफी धनात्मक होता है तो ऐसी सीमावना है कि जब तक तथ्य अन्यथा न दर्शाए यदि लागू पाटनरोधी शुल्क को हटाया जाएगा तो पाटन जारी रहेगा। तथापि यदि जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का कोई निर्यात नहीं होता है तो अन्य संगत कारकों उदाहरणार्थ पाटन की संभावना संबंधी साक्ष्य, यदि कोई हो, की जांच किया जाना अपेक्षित है।

40. घरेलू उद्योग ने बताया है कि निर्णायक समीक्षा के अंतर्गत इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की अवधि समाप्त होने से घरेलू उद्योग को पाटन की पुनरावृत्ति होने की आशंका है। अतः प्राधिकारी की जानकारी में लाए गए ऐसे कारकों की इस बात का पता लगाने के लिए जांच की गई है कि क्या शुल्क की अवधि समाप्त होने पर पाटन की पुनरावृत्ति होने की आशंका है।

41. जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के किसी आयात के अभाव में पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और घरेलू उद्योग द्वारा बताए गए देशों के आपूर्तिकर्ताओं के बीच कथित रूप से आदौतान - प्रदान किए गए ई-मेल की प्रतियों की जांच की है। घरेलू उद्योग ने बताया कि इन संबद्ध देशों के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके ई-मेल में घरेलू उद्योग के लिए संबद्ध वस्तु की उद्धरित कीमतों पर इस मामले में जहां इन देशों से संबद्ध देश के कोई निर्यात नहीं हुए हैं, पाटन की संभावना और क्षति मार्जिन निर्धारित करने का विचार करना चाहिए। घरेलू उद्योग ने ईमेल के आधार पर निर्यात कीमत परिकलित की है और यह संकेत देने के लिए ऊपर यथा उल्लिखित परिकलित सामान्य मूल्य के साथ उसकी तुलना की है कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन की आशंका है।

42. घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के उत्पादकों का यह समूह सीडीआर और डीवीडीआर के उत्पादन में शामिल है। इसके अलावा, सीडीआर और डीवीडीआर दोनों पर पाटनरोधी शुल्क लगता है उन्होंने यह भी बताया कि वह कीमत जिस पर डीवीडीआर का भारत में आयात किया गया है पर भी इन तथ्यों के मद्देनजर प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना चाहिए कि (i) निर्यात देशों में उत्पादकों का यही समूह सीडीआर और डीवीडी दोनों का उत्पादन कर रहा है, (ii) संबद्ध वस्तु और डीवीडी की प्रतिस्थापनीय उत्पादन सुविधाएं हैं; (iii) डीवीडीआर के आयात भी पाटनरोधी शुल्क के अधीन है; (iv)

सीडीआर और डीवीडीआर के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना दर्शाती है कि सीडीआर की कीमतें डीवीडी की कीमतों से लगभग 30 प्रतिशत कम होनी चाहिए। यह भी बताया गया है कि किसी भी संबद्ध देश से किसी निर्यातक/उत्पादक तथा किसी भारतीय आयातक/उत्पादक ने इस समीक्षा जांच का उत्तर नहीं दिया है। इसके अलावा, उन्होंने संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु की क्षमता के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की है जो दर्शाती है कि संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास पर्याप्त क्षमताएं मौजूद हैं :

नाम	निर्यात प्रतिशत
चीन	
शेन्ताउ एसईजेड वु हिंग रेडियो एंड वीडियो कं. लि.	98
शब्दाई संकट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलोजी कं. लि.	21-30
गुआंगजिंग ट्रेडिंग ग्रुप कं. (मकाउ)	61-70
गुआंगझू बनाना डिजीटल कंपनी लिमिटेड	41-50
हांगकांग	
टॉपफोर्ड डेवलपमेंट लि.	91-100
रेडिएस इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट लि.	31-40
ताइवान	
मिन्टेक टेक्नॉलोजी कं. लि.	91-100
वानप्रस्थ कारपोरेशन	91-100
अएल मेजर टेक्नॉलोजी कं. लि.	71-80
मेलोडी टेक्नॉलोजी कारपोरेशन	61-70
सिंगापुर	
सिनर्जी लैब प्रा. लि.	90-100

43. घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि इण्डोनेशिया से इण्डोनेशिया के ऐसे उत्पादक से आयातों की जानकारी मिली है जो सिंगापुर में ऐसे उत्पादक से संबंधित है जिसपर इस समय पाटनरोधी शुल्क लागू है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो कंपनी के पुनः सिंगापुर स्थानांतरित होने की संभावना है। यह भी अनुरोध किया गया कि प्राधिकारी द्वारा पूर्व में की गई जांच से सिद्ध हुआ था कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में भारी गिरावट आई थी और पाटनरोधी शुल्क में असम्मिलित उत्पादों के आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई थी। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो विचाराधीन उत्पाद के आयातों के भारतीय बाजार में सामान्य मूल्य से काफी कम कीमत पर प्रवेश करने की संभावना है।

प्रकटन विवरण के बाद घरेलू उद्योग की टिप्पणियां

44. प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों में घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी को पूर्व में किए गए अपने दावों से संबंधित विचारों को दोहराया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। उसने खासकर सी डी आर और डी वी डी - आर के उत्पादन की अंतर परिवर्तनीय प्रकृति तथा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के यानांतरण से संबंधित मुद्दों को पुनः उठाया है। उसने यह भी कहा है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों के असहयोग की स्थिति में प्राधिकारी को अपनी सूचना निर्धारण सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना अर्थात् घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित किया जाना चाहिए और इसे इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उसने अन्य जांच प्राधिकारियों के कुछ निर्णयों का उल्लेख किया है और यह बताया है कि प्राधिकारी को इस मामले पर उन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए।

प्रकटन विवरण के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां

45. प्रकटन विवरण जारी करने के बाद किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना - प्राधिकारी द्वारा जांच

46. घरेलू उद्योग और इन देशों में संबद्ध वस्तु के आपूर्तिकर्ताओं के बीच कथित रूप से प्राप्त किए भेजे गए ईमेल जिन्हें घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि प्रतियों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि ईमेल के ये आदान - प्रदान उस समय (मुख्यतः जुलाई - अगस्त, 2011 के दौरान) के हैं जब घरेलू उद्योग द्वारा प्राधिकारी के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा, इन ईमेल का आदान प्रदान अधिकांशतः घरेलू उद्योग जो भारत में संबद्ध वस्तु का प्रमुख उत्पादक है और न कि उपभोक्ता या अंतिम प्रयोक्ता है के किसी प्रश्न के उत्तर स्वरूप किया है। इसके अलावा, इन ईमेल में भारत में किसी उपभोक्ता या खुदरा व्यापारी या अंतिम प्रयोक्ता को संबद्ध वस्तु की निर्यात की संभावित कीमत के बारे में कोई सूचना नहीं है। यह भी नोट किया गया कि संबद्ध देशों में प्रचलित संबद्ध वस्तु की कीमत के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा संलग्न की कीमत सूचियों में यह इंगित नहीं है कि इन वस्तुओं को इन कीमतों पर भारत को निर्यात किया जाना संभावित है क्योंकि रिकार्ड में यह सुझाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि इन वस्तुओं का वास्तव में अन्य देशों में और इन कीमतों पर निर्यात किया जा रहा है। इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना भारत में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के संभावित आयात का संकेत नहीं देती है और यह भी कि इसमें ऐसी कोई वास्तविक कीमत नहीं बताई गई है जिस पर इन संबद्ध वस्तुओं के भारत में प्रवेश करने की वास्तविक संभावना है।

47. घरेलू उद्योग के इस अनुरोध के संबंध में कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों का यही समूह सीडीआर और डीवीडीआर के उत्पादन में शामिल है और सीडीआर और डीवीडीआर दोनों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है और वह कीमत जिस पर डीवीडी का भारत में आयात

किया गया है पर भी इन तथ्यों के मद्देनजर प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना चाहिए कि (i) निर्यातक देशों में उत्पादकों का यही समूह सीडीआर ओर डीवीडीआर दोनों का उत्पादन कर रहा है, (ii) संबद्ध वस्तु और डीवीडी की प्रतिस्थापनीय उत्पादन सुविधाएं हैं; यह नोट किया जाता है कि संबद्ध जांच सीडीआर के लिए शुरू की गई है और न कि डीवीडीआर या अन्य ऑप्टिकल डिस्क उपकरण के लिए और प्राधिकारी केवल जांच अवधि और जांच अवधि के बाद के दौरान संबद्ध वस्तु के आयातों की संभावना से संबंधित सूचना पर विचार करेंगे। पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने पर सीडीआर के पाटन की संभावना दर्शाने के आधार के रूप में सीडीआर और डीवीडीआर जैसी अन्य ऑप्टिकल डिस्क के विनिर्माण की समान और प्रतिस्थापनीय लाइनों के मुद्दे पर यह बताया गया है कि किसी उत्पादन लाइन में दो उत्पादों की प्रतिस्थापनीयता भारत में आयात की संभावना का मापदंड नहीं हो सकता है इसके अलावा, डीवीडीआर और सीडीआर अलग-अलग ऑप्टिकल डिस्क हैं और इनकी भिन्न-भिन्न लागतें और कीमतें हैं और केवल इसलिए कि सीडीआर और डीवीडीआर की कुछ विनिर्माण प्रक्रियाएं साझा हैं; भारत में सीडीआर के आयातों की संभावना निर्धारित करने का आधार नहीं हो सकता है।

48. इस मुद्दे के संबंध में कि संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास पर्याप्त क्षमताएं हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने से पाटन में वृद्धि होगी, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी को संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु की बेशी क्षमता के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित क्षमताएं सीडीआर सहित अनेक उत्पादों की समेकित क्षमता संबंधित हैं और उस कीमत के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है जिस पर इन संबद्ध वस्तुओं को अन्य देशों को निर्यात किया गया है जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है। प्राधिकारी को संबद्ध देशों से तीसरे देशों को संबद्ध वस्तु के किसी निर्यात की भी जानकारी नहीं मिली है।
49. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि इण्डोनेशिया से इण्डोनेशिया के ऐसे उत्पादक से आयातों की जानकारी मिली है जो सिंगापुर में ऐसे उत्पादक से संबंधित है जिसपर इस समय पाटनरोधी शुल्क लागू है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो कंपनी के पुनः सिंगापुर स्थानांतरित होने की संभावना है। प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों और ऐसे देशों जिन पर पहले से पाटनरोधी शुल्क लागू है से इतर देशों से कोई आयात नहीं हुए हैं। इसके मद्देनजर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क समाप्ति पर भारत में संबद्ध वस्तु के पाटित कीमत पर आने की काफी कम संभावना प्रतीत होती है।

क्षति और कारणात्मक संबंध**घरेलू उद्योग के विचार**

50 घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अनुरोध किया है :

- क. जैसाकि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री आंकड़ों में गिरावट, लाभ/हानि, नकद प्रवाह, और नियोजित पूंजी पर आय की ऋणात्मक प्रवृत्ति और मालसूची में भारी वृद्धि से सिद्ध होता है घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
- ख. रोजगार और मजदूरी संबंधी मापदंड क्षति नहीं दर्शाते हैं क्योंकि याचिकाकर्ता एक बहु-उत्पाद कंपनी है। मापदंडों की समग्र वृद्धि में पर्याप्त विकृति प्रदर्शित होती है।
- ग. पूर्व में, जब भारी संभावित कीमत कटौती या संभावित कम कीमत या हासकारी प्रभाव की इसी तरह की स्थितियां थी, पाटनरोधी शुल्क को जारी रखा गया है।
- घ. पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने से पाटन और घरेलू उद्योग को तेज क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है समीक्षा जांच का समग्र प्रयोजन यह देखना नहीं है कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाने की जरूरत है बल्कि यह देखना है कि क्या ऐसे शुल्क के अभाव में पाटन में वृद्धि होगी और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।
- ड. संबद्ध देशों की आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित कीमतों या विदेशी उत्पादकों की कीमत सूची यह दर्शाती है कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम होगी। इसके अलावा, यह सूची कीमतें या कीमत प्रस्ताव है और इन कीमतों पर काफी मोलभाव हो सकता है अतः उत्पाद के इन कीमतों से काफी कम कीमतों पर सूचित किए जाने की आशंका है।
- च. वह कीमत जिस पर डीवीडीआर का संबद्ध देशों से भारत में आयात हो रहा है, ऐसी न्यूनतम कीमत है जिस पर संबद्ध देशों में उत्पादक भारतीय बाजार में उत्पाद का निर्यात करेंगे। इस प्रकार भारत को पर्याप्त प्रत्यक्ष पोत लदान के अभाव में, उस कीमत पर विचार करते हुए संभावना का निर्धारण करना उचित है जिस पर डीवीडीआर का भारत को निर्यात हुआ है। यद्यपि डीवीडीआर की कीमतें सीडीआर की कीमत से सामान्यतः अधिक होती है, तथापि यदि कीमत में अंतर की अनदेखी भी की जाए तो डीवीडीआर की आयात कीमत वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति पर पाटन की पर्याप्त संभावना को सद्धि करती है। इसके अलावा, यदि आयात इस कीमत पर होते हैं तो घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन और खराब हो जाएगा।

- छ. बिल्कुल हाल की अवधि में सीडीआर के आयातों की सूचना 3.41 रु की कीमत पर दी गई है। यह कीमत याचिकाकर्ता द्वारा पहले दी गई कीमत आफर से तुलनीय या कम है। इसके अलावा यह कीमत प्रत्येक संबद्ध देश में सामान्य मूल्य से स्पष्टतः कम है। उस कीमत को देखते हुए जिस पर तीसरे देशों से इस समय निर्यात किया जा रहा है, यह स्पष्ट है कि संबद्ध विदेशी उत्पादकों को भारतीय बाजार में बेहतर कीमत नहीं मिल सकती है। ऐसे देशों से आयात इन्हीं कीमतों पर होना संभावित है। यदि संबद्ध देशों से इन्हीं कीमतों पर निर्यात होता है तो घरेलू उद्योग का निष्पादन बहुत खराब हो जाएगा।
- ज. मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के मद्देनजर, संबद्ध देशों से आयात कम हुए हैं। तथापि इण्डोनेशिया से आयातों में जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इण्डोनेशिया से आयात 'पीटी डायनाटेक पेरकासा' से हुए हैं जो इंडोनेशिया में जनरल मेग्नेटिक्स लि. की एक क्षेत्रीय विनिर्माण सुविधा है। जनरल मेग्नेटिक्स लि. कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सिंगापुर में है। ये दोनों कंपनियां संबद्ध हैं। इस प्रकार यद्यपि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के कारण कंपनी इस समय इंडोनेशिया के मार्ग से निर्यात करेगी तथापि यदि पाटनरोधी शुल्क की अवधि समाप्त हो जाती है तो कंपनी इस उत्पाद का निर्यात सिंगापुर से करेगी।
- झ. इस तथ्य को देखते हुए कि सीडीआर और डीवीडीआर विनिर्माण सुविधाएं प्रतिस्थापनीय हैं, समान प्रौद्योगिकी का प्रयोग करती हैं, समान मूल कच्ची सामग्री का उपयोग करती हैं विनिर्माता डीवीडीआर के उत्पादन के लिए इनका प्रयोग करने के लिए अपनी मौजूदा सीडीआर - उत्पादन लाइनों में सरलता से बदलाव कर सकते हैं। अतः सीडीआर और डीवीडीआर की क्षमताओं को पाटन और क्षति की संभावना की जांच करने के लिए प्रतिस्थापनीय रूप में देखना चाहिए। संबद्ध देशों में सीडीआर और डीवीडीआर के विनिर्माता अधिकांशतः समान हैं जो इस तथ्य को और मजबूत बतनाता है कि यदि शुल्क हटाया जाता है तो ये विनिर्माता सीडीआर का पाटन करेंगे, क्योंकि सीडीआर और डीवीडीआर दोनों के आयातों पर इस समय पाटनरोधी शुल्क लागू है।
- ञ. प्राधिकारी ने सीडीआर और डीवीडीआर से संबंधित चार जांच की हैं। सभी जांचों में इन उत्पादों का पर्याप्त पाटन प्रदर्शित हुआ है। जिससे इन उत्पादकों द्वारा अपनाई जा रही पाटन की नीति का पता चलता है। यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो इन निर्यातकों को भारत में उत्पाद का पाटन करने का बेहतर अवसर मिल जाएगा जिससे घरेलू उद्योग का बजार हिस्सा गंवा दिया जाएगा। घरेलू उद्योग पहले से ही उत्पाद की मांग में गिरावट से जूझ रहा है। घरेलू उद्योग के लिए उपलब्ध बाजार अवसर, यदि पाटित आयातों द्वारा कब्जा लिए जाते हैं तो भारतीय उत्पादकों को भारी वित्तीय घाटे उठाने और अपने प्रचालनों को कम करने को मजबूर होना पड़ेगा।

- ट. संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास संबद्ध वस्तु के उत्पादन की विशाल क्षमता है। रिकार्ड के साक्ष्य स्पष्टतया दर्शाते हैं कि संबद्ध देश के उत्पादकों के पास बेशी क्षमताएं मौजूद हैं। यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा में निश्चिन्म रूप से वृद्धि होगी।
- ठ. संबद्ध देशों के अधिकांश उत्पादकों को बेशी क्षमताओं को देखते हुए उत्पादकों के निर्यात पर निर्भर रहना पड़ता है जो बात संबद्ध देशों के विनिर्माताओं के निर्यातोन्मुख होने से साफ तौर पर सिद्ध होती है। यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो इन निर्यातक द्वारा पाटित कीमतों पर भारत को अपने निर्यातों में वृद्धि करने की संभावना है।
- ड. यदि विचाराधीन उत्पाद के आयातों की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जाए तो इस स्पष्टतः पता चलेगा कि पूर्व में विभिन्न देशों द्वारा पाटन की संगत प्रथा रही है। यदि एक समूह के देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो दूसरे समूह के देशों से पाटन शुरू हो जाता है। आयातों में यह बदलाव साफ तौर पर दर्शाता है कि वैश्विक उत्पादकों के पास बेशी क्षमताएं हैं। यदि संबद्ध देशों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो पाटित आयातों के भारतीय बाजार में भारी मात्रा में प्रवेश करने की संभावना है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
- ढ. विचाराधीन उत्पाद के लिए भारतीय बाजार काफी कीमत संवेदी है। यदि कीमत में अधिक अंतरहोता है तो उपभोक्ता अपना स्रोत बदल देते हैं। ऐसे मामले में, बाजार में संबद्ध देशों से ऐसे कम कीमत वाले आयातों की उपलब्धता से उपभोक्ता निश्चित रूप से आयातों को अपनाएंगे जिससे घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- ण. वर्तमान जांच में पूर्ववर्ती तथा हाल के आंकड़ों पर विचार करके भावी निर्धारण के जरिए पाटन और क्षति की संभावना का निर्धारण करना अपेक्षित है। इस प्रकार कानून में ऐसे भावी पूर्वानुमान के लिए कोई पद्धति विशेष या समय सीमा नहीं है।
- त. ग्रेट ब्रिटेन और इंडोनेशिया से पाटित कीमत पर संबद्ध देशों की वस्तुओं के बीच संबद्ध वस्तु के स्थानांतरण का स्पष्ट साक्ष्य है जिसमें शुल्क हटाने से क्षति होने की आशंका है।
- थ. याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त कीमत पेशकश साक्ष्य संबद्ध देशों से निर्यातकों की सीमावित कीमतें दर्शाता है और स्पष्टतया यह दर्शाता है कि ये कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों से काफी कम हैं और इनसे भारी कीमत कटौती होगी। उत्पाद की कीमत संवेदी प्रकृति होने और सीडीआर और डीवीडीआर के लिए उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित की जा

रही कीमतों की प्रवृत्ति को देखते हुए इस बात की पूरी सीमावना है कि घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम करनी पड़ेगी जिससे भारी घाटा होगा।

निर्यातकों, अयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

51. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

52. जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग के अनुरोधों की निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संगत विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जांच की गई है। प्राधिकारी ने समुचित शीर्षों में घरेलू उद्योग के विभिन्न अनुरोधों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन और यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जाता है तो घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की संभावना पर यह निर्धारित करने हेतु विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को क्षति होना जारी रहेगा या उसकी पुनरावृत्ति होगी। इसके अलावा, लागत और कीमतों की दृष्टि से घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन को क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पहुंच मूल्य के संदर्भ में देखा गया है। विधि द्वारा सूचीबद्ध सभी मापदंडों के संबंध में विस्तृत विश्लेषण किया गया है। इन मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

मांग का आकलन

53. विचाराधीन उत्पाद की घरेलू खपत/मांग को घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री मात्रा और भारत में आयातों पर विचार करके निर्धारित किया गया है। घरेलू उद्योग ने द्वितीयक स्रोतों से सौदावार आयात सूचना प्रस्तुत की थी। जांच की प्रक्रिया के दौरान आयातों संबंधी सौदावार सूचना डीजीसीआईएस से मांगी गई थी, जिसे प्राप्त किया गया और उसकी जांच की गई है। प्राधिकारी ने इम्पैक्स स्टेरिस्टिक्स सर्विसेज से याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त सौदावार आयात आंकड़ों की भी जांच की है। ऐसा लगता है कि इम्पैक्स के आंकड़ों में बताए गए अनेक सौदे डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों में दर्ज नहीं हैं। वर्तमान निर्णायक समीक्षा के प्रयोजनार्थ विभिन्न स्रोतों से आयातों की मात्रा और मूल्य निर्धारित करने के लिए इम्पैक्स स्टेरिस्टिक्स डाटा में बताए गए सौदावार आंकड़ों पर भरोसा किया गया है। इस प्रकार आकलित मांग निम्नानुसार है:

विवरण	माप की इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
घरेलू उद्योग की बिक्री	लाख पीस	4,906	4,902	4,257	2,626
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	लाख पीस	2,340	3,000	2,600	1,150
संबंधित देशों से आयात	लाख पीस	0.8	0.17	2.39	-
पाटनरोधी शुल्क लागू वाले देशों से	लाख पीस	307	13	17	3

आयात					
अन्य देशों से आयात	लाख पीस	39	11	3	18
कुल मांग	लाख पीस	7,593	7,926	6,880	3,797
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	91	50

54. यह देखा गया है कि देश में उत्पाद की मांग में भारी गिरावट आई है। यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्रियों में भी जांच अवधि के दौरान भारी कमी आई है।

संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा

55. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से कोई खास वृद्धि हुई है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध -II (ii) में निम्नानुसार व्यवस्था है :

"पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या समग्र रूप से या भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से पाटित आयातों में भारी वृद्धि हुई है।"

56. संबद्ध देशों और अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात समग्र रूप से और उत्पादन और खपत की दृष्टि से निम्नानुसार रहे थे :

विवरण	गाप की इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
आयात					
चीन	लाख पीस	0.80	0.11	2.33	-
हांगकांग	लाख पीस	-	0.00	0.02	-
सिंगापुर	लाख पीस	-	0.06	-	-
ताइवान	लाख पीस	-	-	0.04	-
संबंधित देश	लाख पीस	0.80	0.17	2.39	-
देश जिन पर शुल्क लागू है	लाख पीस	306.91	12.86	16.96	2.52
अन्य देश	लाख पीस	39.40	10.80	3.26	18.33

कुल आयात	लाख पीस	347.11	23.84	22.61	20.85
आयात में बाजार हिस्सा (%)					
चीन	%	0.23	0.45	10.32	-
हांगकांग	%	-	0.01	0.10	-
सिंगापुर	%	-	0.25	-	-
ताइवान	%	-	-	0.16	-
संबद्ध देश	%	0.23	0.72	10.58	-
देश जिन पर शुल्क लागू है	%	88.42	53.97	75.00	12.08
अन्य देश	%	11.35	45.31	14.42	87.92
घरेलू बिक्री	लाख पीस	4,906	4,902	4,257	2,626
प्रवृत्ति	इंडेक्स	100	100	87	54
मांग में बाजार हिस्सा (%)					
संबद्ध देश	%	0.01	0.00	0.03	-
देश जिन पर शुल्क लागू है	%	4.04	0.16	0.25	0.07
अन्य देश	%	0.52	0.14	0.05	0.48
घरेलू उद्योग	%	64.61	61.85	61.88	69.16
अन्य भारतीय उत्पादक	%	30.82	37.85	37.79	30.29
घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में आयात (%)					
संबद्ध देश	%	0.00	0.00	0.02	-
देश जिन पर शुल्क लागू है	%	1.76	0.07	0.12	0.02
अन्य देश	%	0.23	0.06	0.02	0.16

57. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों में समग्र रूप से और भारत में उत्पाद के उत्पादन और खपत की दृष्टि से भारी गिरावट आई है। वस्तुतः जांच अवधि के दौरान किसी भी संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद कोई आयात नहीं हुए हैं। इसके अलावा, संबद्ध देशों से इतर देशों और ऐसे देशों जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है से इतर देशों से भी कोई आयात नहीं हुए हैं। ऐसा लगता है कि भारत में संबद्ध वस्तु की काफी कम मांग है।

कीमत संबंधी प्रभाव

58. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में नियमावली के अनुबंध II(ii) में निम्नानुसार उल्लेख है :

"नियम 18 के उपनियम (2) में यथा उल्लिखित कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की जा रही है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में अत्यधिक मात्रा में कमी करना है या ऐसी कीमत को रोकना है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"

59. चूंकि जांच अवधि के दौरान किसी संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं हुआ इसलिए यह स्पष्ट है कि संबद्ध देशों के आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं कर रहे थे।

कम कीमत पर बिक्री और मंदी

60. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत की तुलना निम्नानुसार दर्शाती है :

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
बिक्री की लागत	रु./पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	इंडेक्स	100	98	90	105
निवल समझने योग्य बिक्री	रु./पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	इकाई	100	95	86	96

61. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत संपूर्ण जांच अवधि में उत्पादन लागत से कम रही है। विशेषतः उत्पादन लागत में 2009-10 तक गिरावट आई और जांच अवधि में वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत ने भी उत्पादन लागत की प्रवृत्ति के समान ही रुझान दिखाया। तथापि वर्ष 2008-10 तक बिक्री कीमत में गिरावट उत्पादन लागत में गिरावट से तीव्र रही थी। इसके अलावा, जांच अवधि के दौरान बिक्री कीमत में वृद्धि उत्पादन लागत में वृद्धि से कम थी।

62. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना के विश्लेषण से पता चलता है कि जांच अवधि में उत्पादन लागत में वृद्धि पॉलीकार्बोनेट की कीमतों में वृद्धि के कारण और न कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण हुई थी। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पॉलीकार्बोनेट ले रहा है और इसलिए पॉलीकार्बोनेट की कीमत में वृद्धि पालीकार्बोनेट की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण हुई थी।

63. उपर्युक्त के मद्देनजर, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के अभाव में कीमत संबंधी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

64. तथापि, निर्णायक समीक्षा जांच में इस बात की जांच करना भी अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की अवधि समाप्त होने पर भारी प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ने की आशंका है। प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना भी अपेक्षित है कि क्या यदि पाटनरोधी शुल्क की अवधि समाप्त होती है तो घरेलू उद्योग को कीमत कटौती, मंदी, नयूनीकरण या कम कीमत पर बिक्री का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी के लिए पाटनरोधी शुल्क के अभाव में संभावित कीमतों पर विचार करना अपेक्षित है। घरेलू उद्योग ने उस कीमत का साक्ष्य दिया है जिस पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने पर वस्तुओं का निर्यात किए जाने की संभावना है। इस प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग और संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के कुछ आपूर्ति कर्ताओं के बीच किए गए ईमेल की प्रतियां उपलब्ध कराई हैं। तथापि जैसा इस जांच परिणाम में बताया गया है, इन ईमेल का आदान प्रदान अधिकांशतः घरेलू उद्योग जो भारत में संबद्ध वस्तु का प्रमुख उत्पादक है और न कि उपभोक्ता या अंतिम प्रयोक्ता है के किसी प्रश्न के उत्तर स्वरूप किया है। इसके अलावा, इन ईमेल में भारत में किसी उपभोक्ता या खुदरा व्यापारी या अंतिम प्रयोक्ता को संबद्ध वस्तु की निर्यात की संभावित कीमत के बारे में कोई सूचना नहीं है। इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना भारत में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के संभावित आयात का संकेत नहीं देती है और यह भी कि इसमें ऐसी कोई वास्तविक कीमत नहीं बताई गई है जिस पर इन संबद्ध वस्तुओं के भारत में प्रवेश करने की वास्तविक संभावना है।

65- घरेलू उद्योग के इस अनुरोध के संबंध में कि आयात इंडोनेशिया से है जो इंडोनेशिया में स्पष्टतः एक उत्पादक है तथा जो सिंगापुर जिस पर इस समय पाटनरोधी शुल्क लागू है, में किसी उत्पादक से संबंधित है और घरेलू उद्योग का यह तर्क कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो कंपनी के पुनः सिंगापुर में शिफ्ट होने की संभावना है, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि संबद्ध देशों से इतर देशों और ऐसे देशों जिन पर पहले से पाटनरोधी शुल्क लागू है, से लगभग कोई आयात नहीं हुए हैं। इसके मद्देनजर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने से भारत में संबद्ध वस्तु के पाटित कीमतों पर आने की काफी कम संभावना प्रतीत होती है।

घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

66. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच करनी होगी। ऐसे उत्पादों के

घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमों में यह भी व्यवस्था है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेशों पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक तथा संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी; वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों समेत सभी संगत आर्थिक कारकों और उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संकेतकों की वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष जांच शामिल होनी चाहिए। घरेलू उद्योग की जांच से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को लगातार क्षति उठानी पड़ी है। चूंकि वर्तमान जांच एक समीक्षा जांच है इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति का आकलन यथा आवश्यक संशोधन आधार पर किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, इस बात की जांच की गई कि क्या मौजूदा उपाय की अवधि समाप्त होने पर घरेलू उद्योग को क्षति होने की आशंका है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

67. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्राएं निम्नानुसार रही हैं :

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
नियोजित क्षमता	लाख पीस	22,135	20,636	15,608	13,489
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	71	61
उत्पादन	लाख पीस	17,457	19,156	14,310	11,440
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	82	66
क्षमता उपयोग	%	78.87	92.83	91.69	84.80
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	109	108
घरेलू बिक्री	लाख पीस	4,906	4,902	4,257	2,626
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	87	54
मांग	लाख पीस	7,593	7,926	6,880	3,797
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	91	50

68. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लागू रहने के बावजूद क्षति अवधि के दौरान उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि उत्पाद की मांग में वैश्विक रूप से और भारत में भारी गिरावट आई है और इसलिए घरेलू उद्योग ने क्षमता कम की है। तथापि याचिकाकर्ता अपनी सीडीआर लाइनों को डीवीडी आर लाइनों में बदलने में समर्थ रहा है एक सुविधा जो वैश्विक रूप से सभी उत्पादकों के पास उपलब्ध नहीं है परंतु घरेलू उद्योग ने जिसे विकसित किया है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की संबद्ध वस्तु की बिक्री और उत्पादन में गिरावट भारत में संबद्ध वस्तु की मांग में भारी कमी के कारण आई है और न कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के किसी आयात के कारण।

लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ

69. घरेलू उद्योग का लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ निम्नानुसार दिए गए हैं :

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
लाभ	रु./पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(127)	(127)	(189)
ब्याज से पहले लाभ	रु./पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(33)	(31)	(15)
नियोजित पूंजी पर आय (एनएफए आधार)	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(476)	(712)	(2,579)
नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	71	27	(21)

70. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को पूरी जांच अवधि के दौरान वित्तीय घाटा उठाना पड़ा है जिसकी मात्रा क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को भारी घाटा हुआ है। जांच अवधि के दौरान वित्तीय घाटों में वृद्धि निविष्टियों की लागत में वृद्धि के कारण अधिक लगती है।

71. निवेश पर आय और नकद लाभ में भी लाभ के जैसा ही रहा है। घरेलू उद्योग को संपूर्ण जांच अवधि में निवेशों पर ऋणात्मक आय प्राप्त हुई है। तथापि घरेलू उद्योग का नकद लाभ 2009-10 तक सकारात्मक रहा था परंतु उसके बाद जांच अवधि में ऋणात्मक रहा था।

72. इस संदर्भ में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के प्रचालनगत निष्पादन में निरंतर भारी गिरावट इस तथ्य के बावजूद हुई है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के कोई आयात नहीं हुए हैं और जांच अवधि में शून्य आयात हुए हैं। वस्तुतः पहले से पाटनरोधी शुल्क लगे हुए देशों तथा संबद्ध देशों से इतर देशों और देशों, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है, से संबद्ध वस्तु के नगण्य आयात हुए हैं।

रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद कंपनी है। अतः रोजगार के स्तर पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा है। रोजगार स्तर की स्थिति और घरेलू उद्योग की मजदूरी निम्नानुसार ही है :

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
रोजगार	संख्या	***	***	***	***
मजदूरी	रु. लाख	***	***	***	***

74. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर में कमी हुई है; जो विचाराधीन उत्पाद की क्षमताओं में कटौती के कारण हो सकती है। इसके अलावा, रोजगार में गिरावट के परिणामस्वरूप, प्रदत्त मजदूरी में भी कमी आई है।

उत्पादकता

75. घरेलू उद्योग की उत्पादकता निम्नांकित तालिका में दी गई है :

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	पीस/संख्या	***	***	***	***
उत्पादकता प्रति दिन	पीस/दिन	***	***	***	***

76. यह नोट किया जाता है कि उत्पादकता में वर्ष 2008-09 तक सुधार हुआ है परंतु उसके बाद गिरावट आई है। तथापि उत्पादकता में गिरावट उतनी अधिक नहीं है जिससे लाभ और निवेश पर आय पर कोई खास प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़े।

माल सूची

77. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की माल सूची के स्तर की जांच की है जिसे निम्नांकित तालिका में दिया गया है :

विवरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
औसत स्टाक	लाख पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	138	122	85

78. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की माल सूची के स्तर में गिरावट आई है।

वृद्धि

79. यह नोट किया जाता है कि मात्रा और कीमत संबंधी मापदंडों की दृष्टि से घरेलू उद्योग की वृद्धि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद नकारात्मक रही है। तथापि यह इस तथ्य के बावजूद भी नकारात्मक रही है कि यह पहले से पाटनरोधी शुल्क लागू देशों तथा संबद्ध देशों से इतर देशों और देशों जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है से संबद्ध वस्तु के नगण्य आयात हुए हैं।

पाटन मार्जिन की मात्रा

80. यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का कोई वर्तमान पाटन नहीं हुआ है क्योंकि संबद्ध देशों से कोई आयात नहीं हुआ है ।

पूंजी जुटाने की क्षमता

81. घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद कंपनी है । याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि यदि पाटित आयातों को जारी रहने दिया जाता है तो घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद में निवेशों में गिरावट आई है जो भारत में संबद्ध वस्तु की भारी गिरावट के मद्देनजर विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षमताओं में कटौती के कारण हुआ है ।

क्षति के जारी रहने के संबंध में प्राधिकारी द्वारा जांच

82. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयातों में भारी गिरावट आई है और जांच अवधि में किसी भी संबद्ध देश से कोई उत्पाद का कोई आयात नहीं हुआ है । वस्तुतः पहले से पाटनरोधी शुल्क वाले देशों तथा संबद्ध देशों से इतर देशों और ऐसे देशों जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है, से संबद्ध वस्तु के बहुत कम आयात हुए हैं । जैसा ऊपर बताया गया है, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात नहीं होने से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण कीमत प्रभाव जारी नहीं है क्योंकि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के लगभग कोई आयात नहीं हुए हैं और जांच अवधि के दौरान शून्य आयात हुए हैं ।

83. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, क्षमता उपयोग, लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय की दृष्टि से विकृति आई है । घरेलू उद्योग के प्रचालनगत निष्पादन में निरंतर और भारी गिरावट इस तथ्य के आलोक में देखी जानी चाहिए कि पहले से पाटनरोधी शुल्क वाले देशों तथा संबद्ध देशों से इतर देशों और ऐसे देशों जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है । इसके अलावा, देश में संबद्ध वस्तु की मांग में क्षति अवधि के दौरान भारी गिरावट आई है । क्षति अवधि के दौरान क्षति संबंधी विभिन्न मापदंडों के उपर्युक्त विश्लेषण के मद्देनजर यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को लगातार क्षति उठानी पड़ी है तथापि, यह निरंतर क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से इतर कारणों के चलते हुई है ।

अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध

84. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है या क्षति होने की संभावना है ।

अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा और कीमतें

85. यह नोट किया जाता है कि अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात भी काफी कम हैं और इनमें से कुछ देशों पर पहले से पाटनरोधी शुल्क लागू है। अतः अन्य देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुआ है।

मांग में कमी और/या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

86. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु की मांग में भारी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि उत्पाद की मांग में यह गिरावट घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार, दोनों में आई है। इस प्रकार ऐसा लगता है कि घरेलू उद्योग को हुई निरंतर क्षति भारत और वैश्विक रूप से उत्पाद की मांग में आई गिरावट का परिणाम है। मांग में यह गिरावट खपत की प्रवृत्ति में बदलाव का परिणाम है। डी वी डी आर और अन्य स्टोरेज मीडिया यंत्रों को अब सी डी आर की तुलना में ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इस प्रकार इस उत्पाद की मांग में गिरावट आई है।

विदेशी और घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

87. संबद्ध वस्तु मुक्त रूप से आयात योग्य है और घरेलू बाजार में कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं हैं। घरेलू उत्पादक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं और साथ ही साथ संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत से भी प्रतिस्पर्धा करती हैं।

प्रौद्योगिकी में विकास

88. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में न तो कोई खास बदलाव हुआ है और न ही इसके भविष्य में बदलने की संभावना है। अतः प्रौद्योगिकी में विकास क्षति का संभावित कारण प्रतीत नहीं होता है।

घरेलू उद्योग की उत्पादकता

89. यह नोट किया जाता है कि उत्पादकता में 2008-09 तक सुधार हुआ है परंतु इसके बाद गिरावट आई है। तथापि, उत्पादकता में यह गिरावट इतनी अधिक नहीं है जिससे लाभों और निवेश पर आय पर कोई खास प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़े।

90. अतः यह निष्कर्ष है कि मांग में गिरावट और घरेलू उद्योग को निरंतर और भारी क्षति सीडीआर से डीवीडी आर और अन्य स्टोरेज मीडिया यंत्रों के लिए खपत में बदलाव का परिणाम है और इससे घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हुई है।

क्षति की संभावना : घरेलू उद्योग के अनुरोध

91. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 (क) (5) के अनुसार पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के प्रश्न की जांच की गई है जिसमें निम्नानुसार व्यवस्था है ।

(5)"इस धारा के अंतर्गत लगाया गया पाटनरोधी शुल्क जब तक उसे समाप्त न किया जाए, इस प्रकार से लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा :

परंतु यदि किसी समीक्षा में केन्द्र सरकार का यह मत हो कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह इस प्रकार से लगाए गए शुल्क की अवधि को समय-समय पर आगे और 5 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है और आगे की ऐसी अवधि इस प्रकार के समय विस्तार के आदेश की तारीख से शुरू होगी ।"

परंतु यह भी कि जहां कोई समीक्षा पूर्वोक्त 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले शुरू की जाती है परंतु अवधि समाप्त होने से पहले किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, वहां ऐसी किसी समीक्षा का परिणाम आने तक एक वर्ष तक की आगामी अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लागू रखे जा सकते हैं ।

92. निरंतर क्षति की जांच के अलावा, घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने की संभावना या उसकी पुनरावृत्ति की भी प्राधिकारी द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना और साक्ष्यों के आधार पर जांच की गई है । घरेलू उद्योग ने बताया है कि निर्णायक समीक्षा के अंतर्गत इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ! अतः प्राधिकारी की जानकारी में लाये गए ऐसे सभी कारकों की यह पता लगाने के लिए जांच की गई है कि क्या शुल्क के समाप्त होने पर क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

93. जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के किसी आयात के अभाव में क्षति की संभावना की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के निम्नलिखित अनुरोधों की जांच की है अर्थात् संबद्ध देशों से निर्यातकों के द्वारा प्रस्तावित कीमतें और ताईवान से निर्यातक की कीमत सूची घरेलू उद्योग द्वारा यह बताया गया है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा प्रस्तावित कीमतों और इसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षति रहित

कीमत के आधार पर संबद्ध देशों से पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, बिक्री कीमत और निर्धारित क्षति रहित कीमत से काफी कम रहेगा।

94. यह भी बताया गया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, बिक्री कीमत, क्षति रहित कीमत से काफी कम रही हैं। अतः यह अनुरोध किया गया है कि यदि वर्तमान उपाय समाप्त होते हैं तो संबद्ध देशों के उत्पादक घरेलू कीमतों में भारी कटौती कर सकते हैं जिससे बजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर काफी अधिक न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और शुल्क की समाप्ति के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उठाए जाने वाले संभावित परिणामी वित्तीय घाटे घरेलू उद्योग द्वारा उठाए जा रहे वित्तीय घाटों से काफी अधिक होंगे। इस संबंध में घरेलू उद्योग ने बताया है कि सी डी आर और डी वी डी आर के उत्पादन में उत्पादकों के समान समूह शामिल हैं। इसके अलावा, सी डी आर और डी वी डी आर दोनों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है। उन्होंने यह भी बताया है कि वह कीमत जिस पर डीवीडी का भारत में आयात किया गया है, पर भी प्राधिकारी द्वारा इन तथ्यों के मद्देनजर विचार किया जाना चाहिए कि (i) निर्यातक देशों में उत्पादकों का एक ही समूह सी डी आर और डी वी डी दोनों का उत्पादन कर रहा है। (ii) संबद्ध वस्तु और डी वी डी की एक समान उत्पादन सुविधाएं हैं। (iii) डी वी डी आर के आयात भी पाटनरोधी शुल्क के अधीन हैं। (iv) सी डी आर और डी वी डी आर के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना यह दर्शाती है कि सी डी आर की कीमतें डी वी डी की कीमतों से लगभग 30 प्रतिशत कम हैं। यह भी बताया गया है कि किसी भी संबद्ध देश के निर्यातक/उत्पादक और किसी भारतीय आयातक/उपभोक्ता ने इस समीक्षा जांच का उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने यह भी बताया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु की बेशी क्षमता मौजूद है। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि आयातों की जानकारी इंडोनेशिया से मिली है जो इंडोनेशिया में एक उत्पादक है तथा जो सिंगापुर जिस पर इस समय पाटनरोधी शुल्क लागू है, में उत्पादक से संबंधित है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो यह कंपनी पुनः सिंगापुर में शिफ्ट हो जाएगी। यह भी बताया गया है कि प्राधिकारी द्वारा की गई पूर्ववर्ती जांच में यह सिद्ध हुआ था कि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद काफी गिरावट आई थी और पाटनरोधी शुल्क के अंतर्गत नहीं शामिल अन्य देशों से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, इन देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद विभिन्न स्रोतों से आयातों की मात्रा में भारी कमी आई है। इस प्रकार यह तर्क दिया गया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो विचाराधीन उत्पाद के आयातों के भारतीय बाजार में सामान्य मूल्य से काफी कम कीमत पर प्रवेश करने की आशंका है।

95. यह बताया गया है कि घरेलू उद्योग पहले से ही निरंतर क्षति का सामना कर रहा है और यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो विचाराधीन उत्पाद के आयातों के घरेलू उद्योग की वर्तमान बिक्री कीमत और उत्पादन लागत से काफी कम कीमतों पर आने की संभावना है। इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने से बाजार में कीमत कटौती होगी और लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ के संबंध में उसके निष्पादन में गिरावट आएगी। इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क हटाने से घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में और विकृति आ जाएगी।

प्रकटन विवरण के बाद घरेलू उद्योग की टिप्पणियां

96. प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों में घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी को पूर्व में किए गए अपने दावों से संबंधित विचारों को दोहराया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। उसने खासकर ई-मेलों और कीमत सूचियों के जरिए इन निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत कीमत और सी डी आर और डी वी डी - आर के उत्पादन की अंतर परिवर्तनीय प्रकृति तथा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के यानांतरण के आधार पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की संभावित कीमत के बारे में मुद्दों को पुनः उठाया है। उसने यह भी कहा है कि भारत में संबद्ध वस्तु की मांग संबद्ध देशों में अन्यत्र आई गिरावट की तुलना में काफी अधिक है। इसके अलावा उन्होंने यह कहा है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों के असहयोग की स्थिति में प्राधिकारी को अपनी सूचना निर्धारण सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना अर्थात् घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित किया जाना चाहिए और इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उसने अन्य जांच प्राधिकारियों के कुछ निर्णयों का उल्लेख किया है और यह बताया है कि प्राधिकारी को इस मामले पर उन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए।

प्रकटन विवरण के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां

97. प्रकटन विवरण जारी करने के बाद किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना-प्राधिकारी द्वारा जांच

98. घरेलू उद्योग और इन देशों में संबद्ध वस्तु के आपूर्तिकर्ताओं के बीच हुए कथित ई मेल जिन्हें घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया है, के संबंध में यह नोट किया जाता है कि ये ई-मेल ऐसे समय (मुख्यतः जुलाई-अगस्त, 2011 के दौरान) हुए हैं, जब घरेलू उद्योग द्वारा प्राधिकारी के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा ये ई मेल अधिकांशतः घरेलू उद्योग जो भारत में संबद्ध वस्तु की प्रमुख उत्पादक है, और न कि कोई उपभोक्ता या अंतिम प्रयोक्ता, से पूछे गए किसी प्रश्न कि उत्तर के रूप में हैं। इसके अलावा, इन ई-मेलों में भारत ने किसी उपभोक्ता या खुदरा व्यापारी या अंतिम प्रयोक्ता को संबद्ध वस्तु के निर्यात की संभावित कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध देशों में प्रचलित संबद्ध वस्तु की कीमत के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा संलग्न कुछ कीमत सूचियां ऐसा संकेत नहीं देती हैं कि इन संबद्ध वस्तुओं की इन कीमतों पर भारत में निर्यात किए जाने की संभावना है क्योंकि रिकॉर्ड में यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि यह संबद्ध वस्तुएं अन्य देशों को इन कीमतों पर निर्यात की जा रही थीं। संबद्ध वस्तु की मांग से संबंधित कारणात्मक संबंध के विश्लेषण से यह स्मरण किया जा सकता है कि देश में संबद्ध वस्तु की मांग में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग ने स्वयं सी डी आर के उत्पाद मिश्रण को बदल दिया है और भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन क्षमता को कम कर दिया है। यह भी नोट किया जाता है कि वस्तुतः भारत में संबद्ध वस्तु में निरंतर गिरावट हो रही है और अनुरोधों तथा प्राधिकारी द्वारा जांच के आधार पर मांग में यह बदलाव बाजार में वैकल्पिक उत्पाद के मौजूद होने के परिणामस्वरूप आया है। उपरोक्त के मद्देनजर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना भारत में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के संभावित आयात का संकेत नहीं देती है और इसमें ऐसी किसी वास्तविक संभावित कीमत का संकेत नहीं है जिस पर संबद्ध वस्तुओं के भारत में प्रवेश और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

99. घरेलू उद्योग के इस अनुरोध के संबंध में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के समान उत्पादक समूह सी डी आर और डी वी डी आर के उत्पादन में शामिल हैं और सी डी आर और डी वी डी आर दोनों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है और वह कीमत जिस पर वह कीमत जिस पर डीवीडी का भारत में आयात किया गया है, पर भी प्राधिकारी द्वारा इन तथ्यों के मद्देनजर विचार किया जाना चाहिए कि (i) निर्यातक देशों में उत्पादकों का एक ही समूह सी डी आर और डी वी डी दोनों का उत्पादन कर रहा है। (ii) संबद्ध वस्तु और डी वी डी की एक समान उत्पादन सुविधाएं हैं। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध जांच सी डी आर के संबंध में शुरू की गई है और न कि डी वी डी आर और अन्य ऑप्टिकल डिस्क के यंत्रों के संबंध में और प्राधिकारी जांच अवधि तथा जांच अवधि के पश्चात की अवधि के लिए ही संबद्ध वस्तु के आयातों की संभावना से संबंधित सूचना पर विचार करेंगे। सी डी आर और अन्य ऑप्टिकल डिस्क जैसे डी वी डी आर के विनिर्माण की समान और प्रतिस्थापनीय लाइनों के मुद्दे को जिसे पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में सी डी आर के पाटन की संभावना दर्शाने के आधार के रूप में बताया गया है, यह उल्लेखनीय है कि किसी उत्पादन में दो उत्पादों की प्रतिस्थापनीयता भारत में आयात की संभावना के लिए मापदंड नहीं हो सकती है। इसके अलावा डी वी डी आर और सी डी आर अलग-अलग ऑप्टिकल डिस्क हैं और इनकी भिन्न-भिन्न लागतें और कीमतें हैं और केवल इसलिए कि सी डी आर और डी वी डी आर की कुछ विनिर्माण प्रक्रियाएं सांझी हैं, भारत में सी डी आर के आयातों की संभावना निर्धारित करने का आधार नहीं हो सकता है।

100. इस मुद्दे के संबंध में कि संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास भारी क्षमताएं मौजूद हैं और यदि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा कि प्राधिकारी की जानकारी में संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु किसी बेशी क्षमता की कोई सूचना नहीं मिली है। यह भी बताया जाता है कि विदेशी उत्पादकों का निर्यातोग्रह्य होना काफी अधिक है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित क्षमताएं सी डी आर सहित अनेक उत्पादों से संबंधित हैं और उस कीमत के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है जिस पर अन्य देशों से इन संबद्ध वस्तु का निर्यात किया गया है। प्राधिकारी को संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर तीसरे देशों को संबद्ध वस्तु के किसी आयात की जानकारी भी नहीं मिली है।

101. घरेलू उद्योग के इस अनुरोध के संबंध में कि आयातों की जानकारी इंडोनेशिया से मिली है जो इंडोनेशिया में एक उत्पादक है तथा जो सिंगापुर जिस पर इस समय पाटनरोधी शुल्क लागू है, में उत्पादक से संबंधित है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो यह कंपनी पुनः सिंगापुर में शिफ्ट हो जाएगी, प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से इतर देशों और ऐसे देशों जिन पर पहले से पाटनरोधी शुल्क लागू है, से लगभग कोई आयात नहीं हुए हैं जिसके मद्देनजर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने से संबद्ध वस्तुओं के भारत में पाटित कीमतों पर आने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की बहुत कम संभावना प्रतीत होती है।

इस सिफारिश से उत्पन्न होने वाले केन्द्र सरकार के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

निष्कर्ष :

102. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का पाटन जारी नहीं है और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है और जांच के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर पाटन की समाप्ति की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है।

103. उपर्युक्त के मद्देनजर यह सिफारिश की जाती है कि इस अधिनियम की धारा 9 (क) (5) के अनुसार पाटनरोधी शुल्क की अवधि को न बढ़ाया जाए जिसे दिनांक 29 जून, 2007 की अधिसूचना सं. 78/2007-सी.शु. द्वारा अधिसूचित और दिनांक 14 नवंबर, 2011 की अधिसूचना सं. 100/2011-सी.शु. द्वारा 3 अक्टूबर, 2012 तक नहीं बढ़ाया जाए ।

आगे की प्रक्रिया

104. इस सिफारिश से उत्पन्न होने वाले केन्द्र सरकार के आदेशों के खिलाफ कोई अपील अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पादक शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी ।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2012

Subject : Sunset Review of Anti dumping duty imposed on Compact Disk Recordable (CDR) in India from China PR, Hong Kong, Singapore and Chinese Taipei—final finding.

No. 15/4/2011-DGAD.— A. BACKGROUND

1. WHEREAS, having regard to above Rules, the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority) initiated an antidumping investigation on 4th April, 2006 into alleged dumping of Compact Discs-Recordable CD-Rs originating in or exported from China PR, Hong Kong, Singapore and Chinese Taipei and provisional antidumping duty was imposed on imports of Compact Discs-Recordable from China PR Hong Kong Singapore and Chinese Taipei vide customs notification no. 105/2006-CUS dated 6th October, 2006 on the basis of the preliminary findings of the Authority dated 28th August 2006. The final findings were notified vide notification dated 2nd April 2007 and the Department of Revenue imposed definitive anti dumping duties on the subject goods from subject country vide notification no. 78/2007-CUS dated 29th June, 2007.
2. And whereas, the Designated Authority, in terms of Section 9A(5) of the Act received a substantiated application from Storage Media Products Manufacturers & Marketers Welfare Association on behalf of the producers of Compact Disk recordable requesting for review, enhancement and continuation of the antidumping duties levied on the subject goods on the grounds that cessation of anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The Designated Authority issued a public notice No. 15/4/2011-DGAD dated 4th October 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping (Sunset Review) investigations, to examine whether the expiry of anti dumping duty would lead to continuation or recurrence of dumping or injury.

3. And whereas antidumping duty as notified vide Notification No. 78/2007-CUS dated 29th June, 2007 was extended up to 3rd October, 2012 vide notification No. 100/2011-Customs dated 14th November, 2011 in terms of Section 9(A)(5) of the Act.
4. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - i) The Authority sent copies of initiation notification dated 4th October 2011 to the Embassy of the subject countries, known exporters/producers from the subject countries, known importers and other interested parties, as per the information available with it. Parties to this investigation were requested to file the questionnaires' responses and make their views known in writing within the prescribed time limit. Copies of the letter and questionnaires sent to the exporters/producers were also sent to the Embassy of the subject countries along with a list of known exporters / producers with a request to advise the exporters/producers from the subject countries to respond to the questionnaires within the prescribed time.
 - ii) The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known producers and/or exporters and the Embassy of the subject countries in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non-confidential application was also made available for other interested parties, on request.
 - iii) The Authority sent a questionnaire to elicit relevant information to the government of subject countries, including known exporters/producers in accordance with the Rule 6(4). However none of the exporters/producers from the subject countries filed response to the questionnaire.
 - iv) Questionnaire was sent to known importers or user for providing necessary information in accordance with Rule 6(4). The Authority provided opportunity to the industrial users of the product under consideration, to furnish information considered relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. However, none of the importers filed response to the questionnaire.
 - v) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigations. The data provided by the domestic industry was sourced from Impex.
 - vi) The Authority held a public hearing on 6th March 2012 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally, which was attended by member of Storage Media Products Manufacturers & Marketers Welfare Association representing domestic industry. The parties attending the public hearing were advised to file written submissions of the information presented

- orally. Designated Authority has considered these written submissions received from interested parties. However, none of the producers/exporters or importers attended the public hearing and therefore has not submitted the written submissions. Arguments raised and information/evidence provided by the interested parties during the course of the investigation, to that extent the same are considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority.
- vii) Arguments raised and information/evidence provided by domestic industry during the course of the investigation, to that extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, shall be appropriately considered by the Authority in the findings.
- viii) The Authority during the course of investigation satisfied itself as to the accuracy of the information supplied upon which these findings are based. For that purpose, the Authority conducted on-the-spot verification of the domestic industry to the extent considered relevant and necessary. Additional/supplementary details regarding injury were sought from the domestic industry, which were also received.
- ix) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on the same have been considered in Final Findings. Following issuance of disclosure statement, the comments have been received only from the domestic industry which have been analysed under the appropriate headings in this subject findings.
- x) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by domestic industry through a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).
- xi) Cost investigations were conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the applicant so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xii) **** represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules on merits.

- xiii) Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2010 to 31st March 2011 (12 months) and has been referred to as the period of investigation (POI). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2007-08, 2008-09, 2009-10 & POI.
- xiv) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigations, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded findings on the basis of the facts available.
- xv) Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has granted confidentiality, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE:

5. The product under consideration in the present investigation is Compact Discs-Recordable (referred to as CD-Rs or subject goods in the present investigation) originating in or exported from China PR, Hong Kong, Singapore and Chinese Taipei (referred to as subject countries in the present investigation).
6. CD-R is a polycarbonate disc containing a spiral groove on one side to guide the laser beam for writing and reading information. The disc is coated on the side with the spiral groove with a very thin layer of vegetable-based organic dye and subsequently with a thin, reflecting layer of silver, a silver alloy or gold. Finally, a protective coating of a photo-polymerizable lacquer is applied on top of the metal reflector and cured with UV-irradiation. Recording on such a disc can be done only once and therefore, the disc is said to be of the type 'WORM' (Write Once Read Many times). The disc is an optical storage medium for digital data or music.

Views of the domestic industry

7. Domestic industry has made following submissions:-
- (i) The present investigation is for the review, enhancement and continuance of anti dumping duty in force against dumping of Compact Discs-Recordable in the Indian market by the producers and/or exporters of China PR. Being a review investigation, product under consideration should be considered the same as has been in the original investigation.
- (ii) The product under consideration in this investigation is Compact Discs-Recordable (CD-Rs). CD-R is a polycarbonate disc containing a spiral groove on one side to guide the laser beam for writing and reading information. The disc is coated on the side with

the spiral groove with a very thin layer of vegetable-based organic dye and subsequently with a thin, reflecting layer of silver, a silver alloy or gold. Finally, a protective coating of a photo-polymerizable lacquer is applied on top of the metal reflector and cured with UV-irradiation. Recording on such a disc can be done only once and therefore, the disc is said to be of the type 'WORM' (Write Once Read Many times). The disc is an optical storage medium for digital data or music

- (iii) The domestic goods are like product to subjects goods exported/produced by exporters with no material difference between the two and being comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification
- (iv) The goods produced by the domestic industry are like article within the meaning of anti dumping Rules.

Views of the Importers, Consumers, Exporters and Other Interested Parties

- 8. None of the importers, consumers, exporters and other interested parties has filed any comment or submissions with regard to product under consideration, like articles and scope of the present investigations

Examination by the Authority

- 9. The product under consideration in the present investigation is Compact Discs-Recordable (referred to as CD-Rs or subject goods in the present investigation) originating in or exported from China PR, Hong Kong, Singapore and Chinese Taipei (referred to as subject countries in the present investigation). The product under consideration is the same as considered in the original investigation.
- 10. Compact Discs-Recordable is classified under Chapter 85 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-headings No 8523. The customs classification is, however, indicative only and not binding on the scope of investigations.
- 11. In the initiation notification, the scope of the product under consideration was specified as follows –

5. As mentioned in the preliminary findings the product under consideration in this investigation is Compact Discs-Recordable (CD-Rs). CD-R is a polycarbonate disc containing a spiral groove on one side to guide the laser beam for writing and reading information. The disc is coated on the side with the spiral groove with a very thin layer of vegetable-based organic dye and subsequently with a thin, reflecting layer of silver, a silver alloy or gold. Finally, a protective coating of a photo-polymerizable lacquer is applied on top of the metal reflector and cured with UV-irradiation. Recording on such a disc can be done only once and therefore, the disc is said to be of the type 'WORM' (Write Once Read Many times). The disc is an optical storage medium for digital data or music.

12. Having regard to the evidence of record and initiation notification, the Authority considers it appropriate to keep the scope of the product under consideration to the same as was considered before.

13. In order to determine whether goods produced by the domestic industry can be considered like article to the goods produced and/or exported from the subject countries, it is noted that the issue has been examined by the Authority and no submissions has been received by the Authority, opposing previous determination of the Authority. The Authority, on the basis of the examination, holds that the material produced by the domestic industry is like article to the goods imported or produced in subject countries within the meaning of the Rules.

DOMESTIC INDUSTRY

Views of the domestic industry

14. The Domestic industry made following submissions regarding domestic industry.

- (i) The application has been filed by Storage Media Products Manufacturers & Marketers Welfare Association on behalf of the producers of Compact Disk recordable. One of its member companies M/s. Moser Baer India Ltd has provided relevant financial information
- (ii) There are seven other known producers of CD-R in India besides the petitioner who do not account for much of the total production and are neither opposing nor supporting the present petition. The petitioner is capable of producing all varieties of CD-R which are like product to imports and thereby accounts for 91.8% of the total production.

Views Of The Exporter, Importers, Consumers And Other Interested Parties

15. None of the other interested parties filed any submissions in this regard.

Examination By The Authority

16. According to the Rule 2 (b), "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected

therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"

17. As per information available on record, production of the "petitioner company" accounts for 91.8% production of the subject goods in India, hence constituting a major proportion in Indian production. The Authority holds that M/s. Moser Baer India Ltd constitutes domestic industry within the meaning of the Rules

OTHER ISSUES

Views of the domestic industry

18. The Domestic industry has submitted as under:-

- (i) The petition was complete in all respect and adequate and accurate evidence was provided to the Authority post initiation.
- (ii) None of the exporters have responded to the questionnaire issued by the Authority. Exporters should therefore be considered non-cooperative as per Rule 6(8) and the Authority should proceed according to the best information available.
- (iii) In view of the existing Anti-dumping duty, the imports from subject countries have declined to low levels during POI. However the imports from Indonesia have increased during period of investigation. It is pertinent to note that the imports from Indonesia are from 'Pt.Dynatech Perkasa' which is a regional manufacturing facility of General Magnetics Limited in Indonesia. General Magnetics Limited is the company with a registered office in Singapore. The two companies are related. Thus, while company is at present exporting through Indonesia in view of the existing Anti-dumping duties, the company would export the product from Singapore in the event of cessation of Anti-dumping duties.

Views of the exporter, importers, consumers and other interested parties

19. None of the other interested parties filed any submissions in this regard.

Examination by the Authority:

20. The Designated has noted the submissions made by interested party and issues have been examined under appropriate headings in this disclosure statement in accordance with the Rules.

DETERMINATION OF CONTINUATION OF DUMPING AND DUMPING MARGIN

DUMPING MARGIN

Views of the domestic industry

21. The domestic industry has submitted as under:

- (i) Petitioner claims that China should be treated as non market economy for the purpose of determination of normal value. Further, there is no claim from a Chinese producer or exporter for market economy treatment. None of the Chinese exporters have filed questionnaire response, nor claimed market economy treatment. Such being the case, question of applying para-8 of Annexure-I and considering whether the Chinese companies are entitled for market economy treatment does not arise.
- (ii) In the original investigations, the Authority has not granted market economy treatment to any of the responding exporter from China PR.
- (iii) There are no imports of the product under consideration in the current POI. In a situation where there are no continued imports, the Authority shall come to a conclusion that there is no continued dumping. However, non existence of continued imports in POI does not imply a need for revocation of anti dumping duties. The same merely implies that the Authority shall determine whether there is likelihood of recurrence of dumping. Petitioner has referred to the practices of other countries as well where anti dumping duties have been extended despite no exports in POI.
- (iv) Likelihood of recurrence of dumping is established from the following :
 - a. Cessation of anti dumping duties is likely to lead to recurrence of dumping & intensified injury to the domestic industry. The entire purpose of the review investigation is not to see whether there is a need for imposition of anti-dumping duty but to see whether in the absence of such duty, dumping would increase and the domestic industry is likely to suffer.
 - b. Evidence of prices being offered by the suppliers from the subject countries or price list of the foreign producers show the landed price of imports shall be significantly below the normal value. Further, these are the list prices or price offers and aggressive negotiations can take place on these prices. The product is therefore likely to be reported at prices significantly below these prices.
 - c. The price at which DVDR is being imported in India from subject countries is the minimum price at which the producers in subject countries would export the product into Indian Market. Thus, in the absence of significant direct shipment to India, it would be appropriate to determine likelihood by considering the price at which DVDR has been exported to India. While DVDR price is normally above CDR price, even if the price difference is ignored, the import price of DVDR establishes significant likelihood of dumping in the event of cessation of present Anti-dumping duties. Further, should the imports be reported at these prices, the performance of the domestic industry would deteriorate further.
 - d. Imports of CDR in the most recent period have been reported at a price of Rs 3.41. This price is comparable or lower than the price offers earlier given by the petitioner. Further this price is clearly below the normal value in each of the

subject countries. Given the price at which material is being at present exported from third countries, it is obvious that the subject foreign producers cannot get the better price in the Indian market. The exports from such countries are likely to be made at these prices. Should the exports from subject countries be made at these prices, the performance of the domestic industry would significantly deteriorate.

- e. In view of the existing anti-dumping duty, the imports from subject countries have declined. However the imports from Indonesia have increased during period of investigation. Imports from Indonesia are from 'Pt.Dynatech Perkasa' which is a regional manufacturing facility of General Magnetics Limited in Indonesia. General Magnetics Limited is the company with a registered office in Singapore. The two companies are related. Thus, while company is at present exporting through Indonesia in view of the existing anti-dumping duties, the company would export the product from Singapore in the event of cessation of anti-dumping duties.
- f. Given the facts that CDR and DVD- R manufacturing facilities are interchangeable, use similar technologies, involves use of same basic raw materials, manufacturers can make simple modifications to their existing CDR production line, in order to use it for production of DVD- R. Therefore, capacities of CDR and DVD-R should be seen interchangeably, for assessing likelihood of dumping and injury. The manufactures of CDR and DVD-R in the subject countries are mostly same which further supports the fact that in the event of revocation of duties, these manufacturers would resort to dumping of CDR as imports of CDR and DVD-R both are at present attracting anti-dumping duty.
- g. The Authority has conducted four investigations relating to CDR & DVD-R. All the investigations have shown significant dumping of these products showing the very policy of dumping being adopted by these producers. In the event of cessation of anti-dumping duty, these exporters will get a greater opportunity to dump the product into India, which shall take away the market share of the domestic industry. The domestic industry is already suffering due to decline in demand of the product. The available market opportunity for the domestic industry, if taken away by the dumped imports, the Indian producers would be forced to suffer heavy financial losses or to reduce their operations.
- h. Producers in subject countries maintain huge capacities to produce subject goods. Record evidences clearly show that there exist excess capacities with the subject countries' producers. In case of revocation of anti dumping duty, the volume of subject goods' imports is bound to increase further.
- i. Majority of the producers in the subject countries have to depend on exports of the product, given surplus capacities; which clearly gets established by the export orientation of the manufacturers in the subject countries. In the event of revocation of duty, these exporters are likely to increase their exports to India at dumped prices.
- j. If the trend of imports of product under consideration is analyzed, it will clearly show that there has been a consistent practice of dumping by different countries in the past. If the anti-dumping duty is imposed on one set of countries, the dumping started from other set of countries. This shift in imports clearly shows that the global producers are faced with surplus capacities. In the event of cessation of anti-dumping duty against subject countries the dumped imports are likely to enter the Indian market at a significant rate causing injury to the domestic industry.
- k. The Indian market for the product under consideration is highly price sensitive. The consumers switch their source if the price difference is found significant. Such

being the case, availability of such low priced imports from subject countries in the market would definitely lead to consumers switching over to the imports which shall cause adverse impact on the domestic industry.

- l. The present investigation requires determination of likelihood of dumping and injury involving prospective determination by consideration of past as well as recent data. As such the law does not provide any particular methodology or time frame for such futuristic prediction.
- m. There is a clear evidence of transshipment of subject goods from amongst subject countries goods at dumped price from Great Britain and Indonesia in which case revocation of duty is likely to cause injury.
- n. The price offer evidence provided by the petitioner shows the likely prices of the exporters from the subject countries and clearly show that these prices are far less than the domestic industry prices and would lead to severe price undercutting. Being the price sensitive nature of the product and seeing the trend of the prices being offered by the producers for CDR and DVDR, in all likelihood, the domestic industry would be forced to reduce its prices which will lead to huge losses.

Views of the other interested parties

22. None of exporter from subject country filed any response with regard to the present investigation.

Examination by the Authority

23. The Authority has noted arguments made by the domestic industry on the methodology for determination of dumping and likelihood thereof. The Authority notes that this being a sunset review investigation, the Authority is required to examine continuation and likelihood of continuation or recurrence of dumping in the event of withdrawal of duty.

Continuation or recurrence of dumping

24. The Authority sent copies of the questionnaire to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1)(c). No response has been received from any of the producer/exporters from subject countries and importers in India on dumping and dumping margin. The Authority, therefore, has no option but to proceed on the basis of best information available on record under Rule 6(8) of AD Rules for non-cooperative exporter which provides that:-

"In a case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the designated authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as it deems fit under such circumstances".

NORMAL VALUE

25. Under section 9A (1) (c) normal value in relation to an article means:

- (i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or
- (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either
 - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

China PR

26. The Authority notes that none of the Chinese producers have cooperated in the present investigation. Para 7 of Annexure I of the AD Rules provides that

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

- 27. The applicant has claimed that normal value should be determined on the basis of the above provisions. The Authority invited comments from all interested parties in accordance with para 7 and 8 of Annexure I.
- 28. The Authority notes that China has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the AD Rules. As per Paragraph 8 of Annexure I of the AD Rules, the presumption of a non-market economy can be rebutted, if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) of Paragraph 8 and establish the facts to the contrary. However,

none of exporters/producers of the subject goods in China have cooperated with the Authority nor provided any information and evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 to consider the following criteria as to whether-

- a. the decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
- b. the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
- c. such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and
- d. the exchange rate conversions are carried out at the market rate.

29. Since none of the Chinese exporters have submitted questionnaire responses including the market economy questionnaire responses and sought to rebut the non-market economy presumption, the Authority is unable to consider whether one or more Chinese producers could be granted market economy status in the present case. The Authority is therefore constrained to proceed with para-7 of Annexure-I for determination of normal value in case of China.

30. The Authority notes that normal value cannot be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information from a producer in that country is not available to the Authority.

31. In view of the above and in the absence of cooperation from Chinese producers, the Authority has considered it appropriate to determine normal value on "any other basis" and has constructed normal value in China on the basis of best estimates of cost of production.

32. The Authority has constructed normal value for the producers in China on the basis of cost of production in India by taking the imports price of the major raw material i.e. Polycarbonate from China PR, duly adjusted.

Hong Kong, Taiwan and Singapore

33. None of the exporters/producers from Hong Kong, Chinese Taipei and Singapore have provided any response or information on the normal value as per the prescribed questionnaire. In absence of the co-operation from exporters the Authority has constructed normal value on the basis of facts available as per Rule-6(8). For this purpose the price of major raw material, Polycarbonate has been taken as per international prevailing prices. Prices of other raw materials, consumption norms for the raw materials and conversion cost have been taken as that of the domestic industry in India. To this financial cost and profit @5% each has been added to construct the normal value. By this methodology, the normal value for Hong Kong, Chinese Taipei and Singapore has been determined.

EXPORT PRICE

34. Under section 9A (1) (b) export price means:

"export price", in relation to an article, means the price of the article exported from the exporting country or territory and in cases where there is not export price or where the export price is unreliable because of association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or a third party, the export price may be constructed on the basis of the price at which the imported articles are first resold to an independent buyer or if the article is not resold to an independent buyer, or not resold in the condition as imported, on such reasonable basis as may be determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

35. The Authority sent questionnaires to all known exporters/producers for the purpose of determination of export price. None of the exporters/producers from subject country filed any information. The Authority notes that there are no known imports of the product concerned from any of the subject countries during the POI. Therefore, actual export price and dumping margin in respect of imports of subject goods into India cannot be determined.

Continuation of Dumping and Dumping margin

36. Accordingly, it is determined that there is no continuation of dumping of the product in the Country during the POI.

Likelihood of recurrence of dumping – Submissions by Domestic Industry

37. The present investigation being a Sunset Review, the question of likelihood of dumping and injury to the domestic industry has been examined by the Designated Authority in terms of Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, which states as under:-

(5)The Anti dumping duty imposed under this section shall, unless revoked either, case to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition;

Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension;

Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the Anti dumping duty may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding one year.

38. In terms of relevant provisions, the following aspects need to be examined in a Sunset review investigation:

- a. Whether the dumping is continuing; and if so, whether it is likely to continue in the event of cessation of the anti-dumping duties;
 - b. In case where dumping did not continue, whether the dumping would recur in the event of cessation of the anti dumping duties;
39. The AD Rules do not prescribe any specific methodology to examine the likelihood of dumping in a Sunset review investigation. However, in case there is a significantly positive dumping margin in respect of exports of the subject goods during the POI; then it is likely that dumping would continue in case of cessation of anti-dumping duty in force, unless the facts state otherwise. However, in case there have been no exports of the subject goods during the POI; then other relevant factors are required to be examined, for instance evidence, if any, regarding likely hood of dumping.
40. The domestic industry has submitted that the requirement under sunset review is to examine whether expiry of anti dumping duty is likely to lead to recurrence of dumping to the domestic industry. Therefore, such factors brought to the notice of the Authority have been examined to ascertain if there is a likelihood of recurrence of dumping in the event of expiry of the duty.
41. For examining the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the absence of any imports of subject goods from subject countries during the POI, the Authority has examined the copies of the emails allegedly exchanged between the domestic industry and suppliers of subject goods in the countries which has been submitted by the domestic industry. The domestic industry has submitted that the price of subject goods quoted by these suppliers from subject countries to the domestic industry in their emails should be taken into account for the purpose of determining the likely hood of dumping and injury margin in the event like in this case where there are no exports of subject goods from these countries. The domestic industry has on the basis of the emails constructed the export price and compared it with the constructed normal value as mentioned above to suggest that there is a likely hood of dumping of subject goods from subject countries in the event of revocation of anti dumping duties.
42. It has also been submitted by the domestic industry that the same set of producers of subject goods from subject countries are involved in production of CDR and DVDR. Further, both CDR and DVDR are attracting anti dumping duty. They have further submitted that the price at which the DVD have been imported into India should also be taken into account by the Authority keeping in view the facts that (i) the same set of producers are producing both CDR and DVD in the exporting countries, (ii) interchangeable production facilities of subject goods and DVD, (iii) DVDR imports are also subject to anti dumping duty, (iv) the information provided by the domestic industry with regard to CDR and DVDR shows that the CDR prices should be about 30% lower than DVD prices. It has also been submitted that none of the exporters/producers from any of the subject countries as well as any of the Indian importers/consumers have responded in this review investigation. Further, they have provided the following information with regard to capacity of subject goods in the

subject countries showing that the producers in subject countries are faced with significant capacities.

Name	Export Percentage
China	
Shantou S.E.Z. Wo Hing Radio & Vedio Co. Ltd	98
Shabghai Suned Electronics Technology Co. Ltd	21-30
Guangxing Trading Group Co. (Macao)	61-70
Guangzhou Banana Digital Company Limited	41-50
Hong Kong	
Topford Development Ltd	91-100
Radiance Enterprise Development Ltd	31-40
Taiwan	
Mintech Technology Co., Ltd.	91-100
Vanprasth Corporation.	91-100
El Mejor Technology Co., Ltd.	71-80
Melody Technology Corp.	61-70
Singapore	
Synergylab Pte Ltd	90-100

43. It has further been submitted by the domestic industry that imports are being reported from Indonesia who is apparently a producer in Indonesia who is related to the producer in Singapore attracting ADD at present. The domestic industry contended that should the anti dumping duty be revoked, the company is likely to shift back to Singapore. It has also been submitted that the investigation earlier conducted by the Authority established that the volume of imports from subject countries declined very significantly after imposition of anti dumping duty and the volume of imports increased from other countries not covered under anti dumping duty. Further, after imposition of anti dumping duty on these countries, the volume of imports from various sources has significantly declined. Thus, it has been contended that should the present anti dumping duty be withdrawn, imports of the product under consideration are likely to enter Indian market at prices significantly below the normal value.

Comments after the disclosure statement by domestic industry

44. In the comments to the disclosure statement, the domestic industry has reiterated their views with regard to their claims made earlier to the Authority that there is a likelihood of recurrence of dumping in the event of cessation of anti dumping duty of subject goods from subject countries. In particular, they have again raised the issues regarding the interchangeable nature of production of CDR and DVD-R and transshipment of the subject goods from other countries. They have added that in the event of non cooperation from exporters from subject countries, the Authority should base their information on the basis of best information available i.e information submitted by the domestic industry and the same can not be rejected. They have added few decisions of the other investigating Authorities and have stated that the Authority should decide the matter taking into account these decisions.

Comments after the disclosure statement by other interested parties

45. No comments have been received from any other interested parties after the issuance of disclosure statement.

Likelihood of recurrence of dumping – Examination by the Authority

46. With regard to copies of the emails allegedly exchanged between the domestic industry and suppliers of subject goods in the countries which has been submitted by the domestic industry, it is noted that these email exchanges date the time (mainly during July-August 2011) when the petition was submitted by the domestic industry to the Authority. Further, these emails have been exchanged largely as a reply of a query from the domestic industry who is a major producer of subject goods in India, and not a consumer or end user. Further these emails do not give any information about the likely price of export of subject goods to any consumer or retailers or end users in India. It is also noted that some of the price lists enclosed by the domestic industry with respect to price of subject good prevailing in subject countries do not indicate the these subject goods would be likely to be exported to India at these prices as there is no evidence on records to suggest that these subject goods are indeed being exported into other countries as well as at these prices. Thus, the information submitted by the domestic industry does not suggest likely import of subject goods from subject countries into India, and also it does not indicate any real likely prices at which these subject goods are likely to enter into India.
47. With regard to submissions by the domestic industry that the same set of producers of subject goods from subject countries are involved in production of CDR and DVDR and both CDR and DVDR are attracting anti dumping duty and the price at which the DVD have been imported into India should also be taken into account by the Authority keeping in view the facts that (i) the same set of producers are producing both CDR and DVD in the exporting countries, (ii) interchangeable production facilities of subject goods and DVD, it is noted that the subject investigations have been initiated on the CDR and not DVDR or other optical disc devices and the Authority would take into account the information concerning likely hood of imports of subject goods only during the POI and post POI period. On the issue of similar and interchangeable lines of manufacture of CDR and other optical disc like DVDR as a ground for indicating likely hood of dumping of CDR if the anti dumping duty is revoked, it is stated that interchangeability of two products in a production line cannot be a criteria for likelihood of importation into India. Further, DVDR and CDR are different optical discs and carry different costs and prices and just because some of the manufacturing processes are common for CDR and DVDR cannot be a ground for determining the likelihood of imports of CDR into India.
48. With regard to the issue that the producers in subject countries are faced with significant capacities and in the event of cessation of anti dumping duty on subject goods from subject countries, it is noted that the Authority has not come across any information with regard to excessive capacity of subject goods in the subject countries. Further, it is noted that the capacities mentioned by the domestic industry pertain to many products including CDR combined together and no information has been submitted with regard to the prices at which these subject goods have been

exported to other countries which are not attracting anti dumping duties. The Authority has also not come across any exports of subject goods from subject countries to third countries at dumped prices.

49. With regard to submissions made by the domestic industry that imports are being reported from Indonesia who is apparently a producer in Indonesia who is related to the producer in Singapore attracting ADD at present and the contention of the domestic industry that should the anti dumping duty be revoked, the company is likely to shift back to Singapore, it is noted by the Authority that there are hardly any imports from countries other than subject countries and countries already attracting the anti dumping duties. In view of this, there appears little likelihood of the subject goods coming into India and also at dumped prices with the cessation of anti dumping duty on subject goods from subject countries.

INJURY & CAUSAL LINK

Views of the Domestic Industry

50. The domestic industry has inter alia submitted as follows:
- a. The Domestic industry has suffered injury as established by decline in production and sales figures of domestic industry, negative trends in profit/loss, cash flow and return on capital employed and significant rise in inventories.
 - b. The parameters of employment and wages do not show injury as the petitioner is a multi-product company. The overall growth parameters show a significant deterioration.
 - c. Anti dumping duty has been continued in the past where there were similar situations of significant likely price undercutting or likely suppressing or depressing effect.
 - d. Cessation of anti dumping duties is likely to lead to recurrence of dumping & intensified injury to the domestic industry. The entire purpose of the review investigation is not to see whether there is a need for imposition of anti-dumping duty but to see whether in the absence of such duty, dumping would increase and the domestic industry is likely to suffer.
 - e. Evidence of prices being offered by the suppliers from the subject countries or price list of the foreign producers show the landed price of imports shall be significantly below the selling price of the domestic industry. Further, these are the list prices or price offers and aggressive negotiations can take place on these prices. The product is therefore likely to be reported at prices significantly below these prices.
 - f. The price at which DVDR is being imported in India from subject countries is the minimum price at which the producers in subject countries would export the product into Indian Market. Thus, in the absence of significant direct shipment to India, it would be appropriate to determine likelihood by considering the price at which DVDR has been exported to India. While DVDR price is normally above CDR price, even if the price difference is ignored, the import price of DVDR establishes significant likelihood of dumping in the event of cessation of present Anti-dumping duties. Further, should the imports be reported at these prices, the performance of the domestic industry would deteriorate further.

- g. Imports of CDR in the most recent period have been reported at a price of Rs 3.41. This price is comparable or lower than the price offers earlier given by the petitioner. Further this price is clearly below the normal value in each of the subject countries. Given the price at which material is being at present exported from third countries, it is obvious that the subject foreign producers cannot get the better price in the Indian market. The exports from such countries are likely to be made at these prices. Should the exports from subject countries be made at these prices, the performance of the domestic industry would significantly deteriorate.
- h. In view of the existing anti-dumping duty, the imports from subject countries have declined. However the imports from Indonesia have increased during period of investigation. Imports from Indonesia are from 'Pt.Dynatech Perkasa' which is a regional manufacturing facility of General Magnetics Limited in Indonesia. General Magnetics Limited is the company with a registered office in Singapore. The two companies are related. Thus, while company is at present exporting through Indonesia in view of the existing anti-dumping duties, the company would export the product from Singapore in the event of cessation of anti-dumping duties.
- i. Given the facts that CDR and DVD- R manufacturing facilities are interchangeable, use similar technologies, involves use of same basic raw materials, manufacturers can make simple modifications to their existing CDR production line, in order to use it for production of DVD- R. Therefore, capacities of CDR and DVD-R should be seen interchangeably, for assessing likelihood of dumping and injury. The manufactures of CDR and DVD-R in the subject countries are mostly same which further supports the fact that in the event of revocation of duties, these manufacturers would resort to dumping of CDR as imports of CDR and DVD-R both are at present attracting anti-dumping duty.
- j. The Authority has conducted four investigations relating to CDR & DVD-R. All the investigations have shown significant dumping of these products showing the very policy of dumping being adopted by these producers. In the event of cessation of anti-dumping duty, these exporters will get a greater opportunity to dump the product into India, which shall take away the market share of the domestic industry. The domestic industry is already suffering due to decline in demand of the product. The available market opportunity for the domestic industry, if taken away by the dumped imports, the Indian producers would be forced to suffer heavy financial losses or to reduce their operations.
- k. Producers in subject countries maintain huge capacities to produce subject goods. Record evidences clearly show that there exist excess capacities with the subject countries' producers. In case of revocation of anti dumping duty, the volume of subject goods' imports is bound to increase further.
- l. Majority of the producers in the subject countries have to depend on exports of the product, given surplus capacities; which clearly gets established by the export orientation of the manufacturers in the subject countries. In the event of revocation of duty, these exporters are likely to increase their exports to India at dumped prices.
- m. If the trend of imports of product under consideration is analyzed, it will clearly show that there has been a consistent practice of dumping by different countries in the past. If the anti-dumping duty is imposed on one set of countries, the dumping started from other set of countries. This shift in imports clearly shows that the global producers are faced with surplus capacities. In the event of cessation of anti-dumping duty against subject countries the dumped imports are likely to enter the Indian market at a significant rate causing injury to the domestic industry.

- n. The Indian market for the product under consideration is highly price sensitive. The consumers switch their source if the price difference is found significant. Such being the case, availability of such low priced imports from subject countries in the market would definitely lead to consumers switching over to the imports which shall cause adverse impact on the domestic industry.
- o. The present investigation requires determination of likelihood of dumping and injury involving prospective determination by consideration of past as well as recent data. As such the law does not provide any particular methodology or time frame for such futuristic prediction.
- p. There is a clear evidence of transshipment of subject goods from amongst subject countries goods at dumped price from Great Britain and Indonesia in which case revocation of duty is likely to cause injury.
- q. The price offer evidence provided by the petitioner shows the likely prices of the exporters from the subject countries and clearly show that these prices are far less than the domestic industry prices and would lead to severe price undercutting. Being the price sensitive nature of the product and seeing the trend of the prices being offered by the producers for CDR and DVDR, in all likelihood, the domestic industry would be forced to reduce its prices which will lead to huge losses.

Views of the Exporters, Importers, Consumers and Other Interested Parties

51. None of the other interested parties have participated in the present investigations. There is no submission by other interested parties.

Examination of the Authority

52. The submissions made by the domestic industry during the course of investigations have been examined by the Designated Authority having regard to the relevant legal provisions. The Authority has examined the various submissions from the domestic industry under appropriate headings. The Authority notes that present investigation being a Sunset Review investigation, the performance of the domestic industry during the injury period and the likelihood of dumping and injury to the domestic industry in the event of the cessation of the anti dumping duty are required to be considered to determine whether expiry of anti dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of injury to the domestic industry. Further, the performance of the domestic industry in terms of cost and prices has been seen in the context of landed value of the subject goods from the subject countries during the injury period and the period of investigation. A detailed analysis has been carried out in respect of all the parameters listed under the law. These parameters are discussed herein under.

Assessment of demand

53. Domestic consumption/demand of the product under consideration has been determined considering sales volume of the domestic industry and other Indian producers and imports into India. The domestic industry had submitted transaction wise import information from secondary sources. During the course of investigation, transaction wise information on imports was sought from DGCI&S, which was received and has been examined. The Authority has also examined the transaction-

wise import data provided by the petitioner from IMPEX Statistics Services. It appears that a significant number of transactions reported in the IMPEX data are not reported in DGCI&S data. The transaction-wise data reported in the IMPEX Statistics data has been relied upon to determine the volume and value of imports from various sources for the purpose of present sunset review. Demand so assessed is as follows –

Particulars	UOM	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
Sales of Domestic Industry	Lac Pcs	4,906	4,902	4,257	2,626
Sales of other Indian Producers	Lac Pcs	2,340	3,000	2,600	1,150
Imports from subject countries	Lac Pcs	0.8	0.17	2.39	-
Imports from Countries attracting ADD	Lac Pcs	307	13	17	3
Import-Other Countries	Lac Pcs	39	11	3	18
Total Demand	Lac Pcs	7,593	7,926	6,880	3,797
Trend	Indexed	100	104	91	50

54. It is seen that demand of the product in the country has shown a significant decline. It is also noted that sales of the domestic industry and other domestic producers have also declined significantly during the injury period.

Volume of Dumped Imports from subject imports

55. With regard to volume of the dumped imports, it has been examined whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure II (ii) of the anti dumping rules provides as under:

“While examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been significant increase in the dumped imports either in absolute terms or relative in production or consumption in India”

56. Imports of the product under consideration from subject countries and other countries in absolute terms and in relation to production and consumption were as follows –

Particular	UQM	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
Imports					
China	Lac Pcs	0.80	0.11	2.33	-
Hong Kong	Lac Pcs	-	0.00	0.02	-
Singapore	Lac Pcs	-	0.06	-	-
Taiwan	Lac Pcs	-	-	0.04	-

Subject Countries	Lac Pcs	0.80	0.17	2.39	-
Country Attracting Duties	Lac Pcs	306.91	12.86	16.96	2.52
Other Countries	Lac Pcs	39.40	10.80	3.26	18.33
Total Imports	Lac Pcs	347.11	23.84	22.61	20.85
Market Share in Imports (%)					
China	%	0.23	0.45	10.32	-
Hong Kong	%	-	0.01	0.10	-
Singapore	%	-	0.25	-	-
Taiwan	%	-	-	0.16	-
Subject Countries	%	0.23	0.72	10.58	-
Countries attracting duties	%	88.42	53.97	75.00	12.08
Other countries	%	11.35	45.31	14.42	87.92
Domestic sales	Lac Pcs	4,906	4,902	4,257	2,626
Trend	Indexed	100	100	87	54
Market share in demand (%)					
Subject Countries	%	0.01	0.00	0.03	-
Countries attracting duties	%	4.04	0.16	0.25	0.07
Other countries	%	0.52	0.14	0.05	0.48
Domestic industry	%	64.61	61.85	61.88	69.16
Other Indian producers	%	30.82	37.85	37.79	30.29
Imports in relation to production of domestic industry (%)					
Subject Countries	%	0.00	0.00	0.02	-
Country Attracting Duties	%	1.76	0.07	0.12	0.02
Other Countries	%	0.23	0.06	0.02	0.16

57. It is noted that there is a significant decline in imports of subject goods from subject countries in absolute terms and in relation to production and consumption of the product in India. In fact, there were no imports of the product under consideration from any of the subject countries during the POI. Further, there are hardly any imports from countries other than subject countries and countries other than attracting anti dumping duties also. It appears that there is little demand for the subject goods into India.

Price Effect

58. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules states as under:

"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."

59. Since there were no imports of the product under consideration from any of the subject countries during the POI, it is evident that the imports from subject countries were not undercutting the domestic industry prices.

Price suppression and depression

60. Comparison of cost of production and selling price of the domestic industry over the injury period shows as follows –

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
Cost of sales	Rs/pc	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	90	105
Net sales realization	Rs/pc	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	86	96

61. It is noted that the selling price of the domestic industry has always remained below cost of production during the entire injury period. In particular, the cost of production declined up to 2009-10 and increased in POI. Selling price of the domestic industry has also followed the same trend as that of cost of production. However, till 2008-10, the decline in selling price was steeper than the decline in cost of production. Further, the increase in the selling price in the investigation period was lower than the increase in cost of production.
62. Analysis of information provided by the domestic industry showed that the increase in the cost of production in POI was due to increase in the prices of polycarbonate and

not on account of any imports of subject goods from subject countries. It is further noted that the domestic industry is sourcing polycarbonate from international market and therefore the increase in polycarbonate price was due to international increase in the prices of polycarbonate.

63. In view of the above, it is noted that there is no price effect in the absence of subject goods imports from subject countries.
64. However, in a sunset review investigation, it is also required to be examined whether there is likelihood of significant adverse price effect in case of expiry of anti dumping duty. The Authority is further required to examine whether the domestic industry is likely to face price undercutting, depression, suppression and underselling in the event of expiry of anti dumping duties. For the purpose, the Authority is required to consider the likely prices in the absence of anti dumping duty. The domestic industry has provided evidence of the price at which the goods are likely to be exported in the event of cessation of anti dumping duty. For the purpose, the domestic industry has provided copies of the emails exchanged between the domestic industry and some suppliers of subject goods from subject countries. However, as stated in this finding, these emails have been exchanged largely as a reply of a query from the domestic industry who is a major producer of subject goods in India, and not a consumer or end user. Further these emails do not give any information about the likely price of export of subject goods to any consumer or retailers or end users in India. Thus, the information submitted by the domestic industry does not suggest likely import of subject goods from subject countries into India, and also it does not indicate any real likely prices at which these subject goods are likely to enter into India.
65. With regard to submissions made by the domestic industry that imports are being reported from Indonesia who is apparently a producer in Indonesia who is related to the producer in Singapore attracting ADD at present and the contention of the domestic industry that should the anti dumping duty be revoked, the company is likely to shift back to Singapore, it is noted by the Authority that there are hardly any imports from countries other than subject countries and countries already attracting the anti dumping duties. In view of this, there appears little likelihood of the subject goods coming into India and also at dumped prices with the cessation of anti dumping duty on subject goods from subject countries.

Economic Parameters Relating To the Domestic Industry

66. Annexure II to the AD Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered continued injury. The present investigations being a review investigations, injury to the domestic

industry is required to be assessed on mutates mutandis basis. Further, it was examined whether expiry of existing measure is likely to lead to injury to the domestic industry. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

67. Capacity, production, capacity utilization and sales volumes of the domestic industry have been as under:-

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
Installed capacity	Lac Pcs	22,135	20,636	15,608	13,489
Trend	Indexed	100	93	71	61
Production	Lac Pcs	17,457	19,156	14,310	11,440
Trend	Indexed	100	110	82	66
Capacity utilization	%	78.87	92.83	91.69	84.80
Trend	Indexed	100	118	109	108
Domestic sales	Lac Pcs	4,906	4,902	4,257	2,626
Trend	Indexed	100	100	87	54
Demand	Lac Pcs	7,593	7,926	6,880	3,797
Trend	Indexed	100	104	91	50

68. It is noted that production and sales declined during the injury period despite anti-dumping duty in force. The petitioner contended that there is significant decline in demand of the product globally and in India and therefore the domestic industry has reduced its capacity. However, the petitioner was able to convert its CDR lines into DVD-R, a flexibility that is not available to all the producers globally but capability that the domestic industry has developed. It is noted that the decline in the sales and production of subject goods domestic industry is because of significant decline in the demand of subject goods in India and not due to any imports of subject goods from subject countries.

Profits, return on investment and cash profit

69. Profits, return on investment and cash profit of the domestic industry are given as under:

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
Profit	Rs/Pc	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(127)	(127)	(189)
Profit before interest	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(33)	(31)	(15)
Return on capital employed (NFA basis)	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(476)	(712)	(2,579)
Cash profit	Rs.Lacs	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	71	27	(21)
-------	---------	-----	----	----	------

70. It is noted that the domestic industry has suffered financial losses throughout the injury period, extent of which increased throughout the injury period. During POI, Domestic Industry has suffered significant losses. The increase in financial losses during the POI appears to be significant which is due to increase in input prices.
71. Return on investment and cash profits have followed the same trend as that of profits. The domestic industry had negative return on investment throughout the injury period. However the cash profits of the domestic industry remained positive till 2009-10 but thereafter was negative during period of investigation.
72. It is noted in this context that continued significant decline in the operating performance of the domestic industry has happened despite the fact that there is hardly any imports of subject goods during the injury period and nil imports during the POI. In fact, there are negligible imports of subject goods from countries already attracting anti dumping duties as well as countries other than subject countries and not attracting anti dumping duties.

Employment, wages and Productivity

73. The Authority notes that the domestic industry is multi product company. Therefore, there is no direct effect on employment levels. Status of employment levels and wages of the domestic industry has been as under.

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
Employment	Nos	***	***	***	***
Wages	Rs.Lacs	***	***	***	***

74. It is noted that employment level of the domestic industry has declined, which could be because of reduction of capacities in the product under consideration. Further, as a consequence of decline in employment, wages paid also declined.

Productivity

75. The productivity of the domestic industry is given in the following table:

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
Productivity per employee	Pcs/Nos	***	***	***	***
Productivity per day	Pcs/Day	***	***	***	***

76. It is noted that productivity improved till 2008-09 but declined thereafter. However, the decline in productivity is not so significant as to have had significant adverse price effect on profits and return on investment.

Inventories

77. Designated Authority has examined the inventory level of the domestic industry, which is given in the following table:-

Particulars	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Average stock	Lac Pcs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	138	122	85

78. It is noted that the inventory levels with the domestic industry declined.

Growth

79. It is noted that growth of the domestic industry in terms of volume and price parameters has remained negative despite imposition of anti dumping duties. However, the same has been negative despite the fact that there are negligible imports of subject goods from countries already attracting anti dumping duties as well as countries other than subject countries and not attracting anti dumping duties.

Magnitude of Dumping Margin

80. It is noted that there is no current dumping of subject goods during the POI as there are no imports from subject countries.

Ability to raise capital

81. The domestic industry is a multi product company. The petitioner has contended that if dumped imports are allowed to continue, its adverse impact would surely impact domestic industry's ability to raise capital investments. It is noted that the investments in the product under consideration have declined, which is due to curtailment in capacities deployed for the product under consideration in view of the significant decline of the subject goods in India.

Examination by Authority on continuation of injury

82. It is noted that imports of the product under consideration declined significantly over the injury period and there were no imports of the product in the POI from any of the subject countries. In fact, there are very little imports of subject goods from countries already attracting anti dumping duties as well as countries other than subject countries and not attracting anti dumping duties. As stated above, in the absence of imports of subject goods from subject countries, there is no continued price effect on account of imports of subject goods from subject countries as there is hardly any imports of subject goods during the injury period and nil imports during the POI.

83. It is noted that performance of the domestic industry has deteriorated in terms of production, domestic sales, capacity utilization, profits, cash profits and return on capital employed. The continued and significant deterioration in the operating performance of the domestic industry has to be seen in the light of fact that there are very little imports of subject goods from countries already attracting anti dumping duties as well as countries other than subject countries and not attracting anti dumping duties. Further, the demand of subject goods in the country has significantly declined

during the injury period. In view of the above analysis of various injury parameters during injury period, it is noted that the domestic industry has suffered continued injury, however, the continued injury is because of factors other than imports of subject goods from subject countries.

Other Known Factors And Causal Link

84. The Authority has examined whether other listed known factors could have caused or are likely to cause injury to the domestic industry.

Volume and prices of imports from other sources

85. It is noted that the imports of the product under consideration from other countries are also quite low and some of these countries are already attracting anti dumping duties. The imports from other countries could not have therefore caused injury to the domestic industry.

Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

86. It is noted that the demand of the subject goods has shown significant decline. The domestic industry has also submitted that there is significant decline in demand for the product both in the domestic and international market. It thus appears that the continued injury to the domestic industry is a result of decline in demand for the product in India and globally. This decline in demand appears to a result of shift in consumption pattern. DVDR and other storage media devices are increasingly preferred over to CDR, thus leading to decline in demand for the product.

Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

87. The subject goods are freely importable and there are no trade restrictive practices in the domestic market. The subject goods produced by the domestic producer compete among one another and at the same time compete with the landed price of the subject goods.

Developments in technology

88. It is noted that the technology for production of the subject goods has neither undergone any material change nor is likely to change in future. Developments in technology, therefore, do not appear to be a possible factor of injury.

Productivity of the Domestic Industry

89. It is noted productivity improved till 2008-09 but declined thereafter. However, the decline in productivity is not so significant as to have had significant adverse price effect on profits and return on investment.

90. It is thus concluded that decline in demand and continued and significant injury to the domestic industry is as a result of shift in consumption pattern from CDR to DVDR and other storage media devices has caused continued injury to the domestic industry.

Likelihood of Injury: Submissions by domestic industry

91. The present investigation being a Sunset Review, the question of likelihood of dumping and injury to the domestic industry has been examined by the Designated

Authority in terms of Section 9 (A) (5) of the Customs Tariff Act, which states as under:-

(5) The Anti dumping duty imposed under this section shall, unless revoked either, case to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition;

Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension;

Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the Anti dumping duty may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding one year.

92. In addition to the examination of continued injury, likelihood of continued or recurrence of injury to the domestic industry has also been examined by the Authority on the basis of information and evidence presented by domestic industry during the course of the investigations. The domestic industry has submitted that the requirement under sunset review is to examine whether expiry of anti dumping duty is likely to lead to continuance or recurrence of injury to the domestic industry. Therefore, all such factors brought to the notice of the Authority have been examined to ascertain if there is a likelihood of continuation or recurrence of injury in the event of expiry of the duty.
93. For examining the likely hood of injury in the absence of any imports of subject goods from subject countries during the POI, the Authority has examined the following submissions of domestic industry i.e Prices offered by the exporters of the exporters from subject countries and the price list of the exporter from Taiwan. It has been submitted by the domestic industry that on the basis of prices offered by the exporters of the subject countries and non injurious price determined for the domestic industry during the same period, the landed value of imports from the subject countries without the antidumping duty would have been significantly below the cost of production, selling price and non injurious price determined for the domestic industry.
94. It has also been submitted that the landed price of imports of imports of subject goods from subject countries would have been significantly below cost of production, selling price and non injurious price of the domestic industry. Therefore, it has been submitted that should the present measure expire, the producers in subject countries are likely to undercut the domestic prices to a significant degree, which shall have significant depressing effect on the prices of the domestic industry in the market and consequent financial losses that the domestic industry is likely to suffer in the event of expiry of duty shall be significantly higher than the financial losses being suffered by the domestic industry. In this regard, the domestic industry has submitted that the same sets of producers are involved in production of CDR and DVDR. Further, both CDR and DVDR are attracting anti dumping duty. They have further submitted that the price at which the DVD have been imported into India should also be taken into account by the Authority keeping in view the facts that (i) the same set of producers

are producing both CDR and DVD in the exporting countries, (ii) interchangeable production facilities of subject goods and DVD, (iii) DVDR imports are also subject to anti dumping duty, (iv) the information provided by the domestic industry with regard to CDR and DVDR shows that the CDR prices should be about 30% lower than DVD prices. It has also been submitted that none of the exporters/producers from any of the subject countries as well as any of the Indian importers/consumers have responded in this review investigation. Further, they have also submitted that there is excess capacity of subject goods in the subject countries. It has further been submitted by the domestic industry that imports are being reported from Indonesia who is apparently a producer in Indonesia who is related to the producer in Singapore attracting ADD at present. The domestic industry contended that should the anti dumping duty be revoked, the company is likely to shift back to Singapore. It has also been submitted that the investigation earlier conducted by the Authority established that the volume of imports from subject countries declined very significantly after imposition of anti dumping duty and the volume of imports increased from other countries not covered under anti dumping duty. Further, after imposition of anti dumping duty on these countries, the volume of imports from various sources has significantly declined. Thus, it has been contended that should the present anti dumping duty be withdrawn, imports of the product under consideration are likely to enter Indian market at prices significantly below the normal value.

95. It has been submitted that the domestic It has been submitted that the domestic industry is already suffering continued injury and should the present anti dumping duty be withdrawn, imports of the product under consideration are likely at prices significantly below the current selling price and cost of production of the domestic industry. Thus, revocation of anti dumping duty shall cause price undercutting in the market and its performance will deteriorate further in respect of profits, return on investment and cash profits. Thus, cessation of anti dumping duty shall lead to further deterioration in the performance of the domestic industry.

Comments after the disclosure statement by domestic industry

96. In the comments to the disclosure statement, the domestic industry has reiterated their views with regard to their claims made earlier to the Authority that there is a likelihood of recurrence of injury in the event of cessation of anti dumping duty of subject goods from subject countries. In particular, they have again raised the issues regarding likely prices of the subject goods from subject countries on the basis of prices offered by these exporters through emails and price lists and interchangeable nature of production of CDR and DVD-R and transshipment of the subject goods from other countries. They have added that the decline in the demand of subject goods in India is much higher than the decline elsewhere in the subject countries. Further, they have added that in the event of non cooperation from exporters from subject countries, the Authority should base their information on the basis of best information available i.e information submitted by the domestic industry and the same can not be rejected. They have added few decisions of the other investigating Authorities and have stated that the Authority should decide the matter taking into account these decisions.

Comments after the disclosure statement by other interested parties

97. No comments have been received from any other interested parties after the issuance of disclosure statement.

Likelihood of recurrence of Injury – Examination by the Authority

98. With regard to copies of the emails allegedly exchanged between the domestic industry and suppliers of subject goods in the countries which has been submitted by the domestic industry, it is noted that these email exchanges date the time (mainly during July-August 2011) when the petition was submitted by the domestic industry to the Authority. Further, these emails have been exchanged largely as a reply of a query from the domestic industry who is a major producer of subject goods in India, and not a consumer or end user. Further these emails do not give any information about the likely price of export of subject goods to any consumer or retailers or end users in India. It is also noted that some of the price lists enclosed by the domestic industry with respect to price of subject good prevailing in subject countries do not indicate that these subject goods would be likely to be exported to India at these prices as there is no evidence on records to suggest that these subject goods are indeed being exported into other countries as well and at these prices. It may be recalled from the analysis in the casual link concerning demand of the subject goods that the demand of the subject goods in the country has gone down and domestic industry itself has changed the product mix of CDR and reduced the production capacity of the subject goods In India. In fact, it is also noted that the there is continuous decline of the subject goods in India and based on the submissions and examination by the Authority, the change in the demand has resulted because of alternative product being available in the market. In view of the above, the information submitted by the domestic industry does not suggest likely import of subject goods from subject countries into India, and also it does not indicate any real likely prices at which these subject goods are likely to enter into India and cause injury to the domestic industry.
99. With regard to submissions by the domestic industry that the same set of producers of subject goods from subject countries are involved in production of CDR and DVDR and both CDR and DVDR are attracting anti dumping duty and the price at which the DVD have been imported into India should also be taken into account by the Authority keeping in view the facts that (i) the same set of producers are producing both CDR and DVD in the exporting countries. (ii) interchangeable production facilities of subject goods and DVD, it is noted that the subject investigations have been initiated on the CDR and not DVDR or other optical disc devices and the Authority would take into account the information concerning likely hood of imports of subject goods only during the POI and post POI period. On the issue of similar and interchangeable lines of manufacture of CDR and other optical disc like DVDR as a ground for indicating likely hood of dumping of CDR if the anti dumping duty is revoked, it is stated that interchangeability of two products in a production line cannot be a criteria for likelihood of importation into India.. Further, DVDR and CDR are different optical discs and carry different costs and prices and just because some of the manufacturing processes are common for CDR and DVDR cannot be a ground for determining the likelihood of imports of CDR into India.

100. With regard to the issue that the producers in subject countries are faced with significant capacities and in the event of cessation of anti dumping duty on subject goods from subject countries, it is noted that the Authority has not come across any information with regard to excessive capacity of subject goods in the subject countries. It has been also submitted that the export orientation of the foreign producers is quite high. In this regard, it is noted that the capacities mentioned by the domestic industry pertain to many products including CDR combined together and no information has been submitted with regard to the prices at which these subject goods have been exported to other countries. The Authority has also not come across any exports of subject goods from subject countries to third countries at dumped prices.
101. With regard to submissions made by the domestic industry that imports are being reported from Indonesia who is apparently a producer in Indonesia who is related to the producer in Singapore attracting ADD at present and the contention of the domestic industry that should the anti dumping duty be revoked, the company is likely to shift back to Singapore, it is noted by the Authority that there are hardly any imports from countries other than subject countries and countries already attracting the anti dumping duties. In view of this, there appears little likelihood of the subject goods coming into India and also at dumped prices with the cessation of anti dumping duty on subject goods from subject countries and injuring the domestic industry.

Conclusions:

102. The Authority notes that there is no continuation of dumping of subject goods from subject countries and there is no likelihood of recurrence of dumping of subject goods from subject countries and on the basis of the examination, it is concluded that cessation of anti-dumping duty on subject goods from subject countries is not likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to domestic industry.
103. In view of the above, it is recommended not to extend the antidumping duty in terms of Section 9(A)(5) of the Act which was notified vide Notification No. 78/2007-CUS dated 29th June, 2007 and extended up to 3rd October, 2012 vide notification No. 100/2011-Customs dated 14th November, 2011.

Further procedures

104. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority